रजिस्ट्रर्ड सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, 18 अक्तूबर, 1975/आश्विन 26, 1897

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1975/ASVINA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 30th April 1975 :—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
124	का०आ० 165 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं० का०आ० 76 (ई) दिनांक 4 फरवरी, 1975 का 31 जुलाई, 1975 तक प्रवृत्त करना ।
	S.O. 165 (E) dt. 1st April 1975	Ministry of Agriculture and Irrigation	Enforcement of Notifn. S.O. 76 (E) of 4th Feb. 1975 upto 31st July, 1975, by the Central Govt.
125	का०आ० 166 (अ) दिनांक 1 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 आगे संशोधन करना ।
	S.O. 166 (E) dated 1st April, 1975	Ministry of Commerce	Further amendments of Exports (Control) Order, 1958 by the Central Govt.
126	का०आ० 167 (अ) दिनांक 3 अप्रैल, 1975	भारत परिसीमन आयोग	बिहार राज्य के संसदीय तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में विसम्मत टिप्पण-आयोग की प्रस्थापनाओं का प्रकाशित किया जाना ।
	S.O. 167 (E) dated 3rd April, 1975	Delimitation Commission India.	Note of dissant to the delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies in the State of Bihar—Publication of the Commission Proposals.
127	एस०ओ० 168 (अ)/आई०ई०सी०ए०/3-4-75 दिनांक 7 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 का और आगे संशोधन करना ।
	S.O. 168 (E)/I. C.E.A./3-4-75 dated the 7th April, 1975.	Ministry of Commerce	Further amendment of Imports (Control) Order, 1955 by the Central Govt.

1	2	3
128 एस०ओ० 169 (अ) आई०ई०सी०ए० 3-5-75 दिनांक 7 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात नियंत्रण आदेश, 1955 का और आगे संशोधन करना ।
S.O. 169(E)/IECA/3-5-75 dated the 7th April 1975	Ministry of Commerce	Further amendment of Imports (Control) Order, 1955 by the Central Govt.
फा०आ० 170 (अ) दिनांक 7 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4 का और आगे संशोधन करना ।
S.O. 170 (E) dated 7th April 1975	Ministry of Commerce	Further amendment to the Open General Licence No. IV by the Central Govt.
129 का०आ० 171 (अ) दिनांक 7 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 का और आगे संशोधन ।
S.O. 171 (E) dated 7th April, 1975.	Ministry of Commerce	Further amendment of Exports (Control) Order, 1968.
130 का०आ० 172 (अ) दिनांक 9 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 का और आगे संशोधन करना ।
S.O. 172(E) dated 9th April, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Further amendment of Cement Control Order, 1967 by the Central Govt.
131 का०आ० 173 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर० ए०/ 75 दिनांक 9 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	आदेश सं० का०आ० सं० 250 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी० आर०ए०/73, दिनांक 27 अप्रैल, 1973 का 26 अप्रैल, 1975 से एक वर्ष अतिरिक्त के लिए बढ़ाया जाना ।
S.O. 173(E)/18IB/IDRA/75 dated 9th April, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supply.	Extension of Order No. S.O. No. 250 (E) /18FB/IDRA/73, dated the 26th April, 1973 for a further period of One year from the 26 th April, 1975.
132 का०आ० 174 (अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 का और आगे संशोधन करना ।
S.O. 174(E) dated 10th April, 1975.	Ministry of Commerce	Further amendment of Exports (Control) Order, 1968 by the Central Govt.
133 S.O. 175(E) dated 11th April, 1975.	Delimitation Commission of India.	Publication of proposals for the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituancies together with the disserting proposals in the West Bengals State by the Delimitation-Commission
134 का०आ० 176 (अ) दिनांक 14 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जी० रामानाथन्, उप सचिव को नियंत्रक नियुक्त करना ।
S.O. 176 (E) dated 14th April, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Appointment of Shri G. Ramanath, Deputy Secretary as Controller by the Central Govt.
135 का०आ० 177 (अ) दिनांक 14 अप्रैल, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	निर्वाचन प्रतीक अधिसूचना सं० 56/75-i (का०आ० 61 (ई) दिनांक 31 जनवरी 1975 का संशोधन करना ।
S.O. 177(E) dated 14th April, 1975	Election Commission of India,	Amendment of Notification No. 56/75-I [S.O. 61 (E)] dated 31st January 1975 regarding Election Symbols.
136 का०आ० 178 (अ) दिनांक 14 अप्रैल, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना सं० 56/75-ii (का०आ० 68 (ई) दिनांक 1 फरवरी, 1975 का संशोधन करना ।
S.O. 178(E) dated 14th April, 1975	Election Commission of India.	Amendment of Notification No. 56/75-II [S.O. 68(E)] dated 1st February, 1975 by the Election Commission of India,
137 का०आ० 179 (अ) दिनांक 15 अप्रैल, 1975	वित्त मंत्रालय	श्री आर०एल० मलहोत्रा विशेष कार्य अधिकारी को प्रयोजनार्थ अधिकारी नियुक्त करना ।
S.O. 179(E) dated the 15th April, 1975	Ministry of Finance	Appointment of Shri R.L. Malhotra, Officer as Special duty as authority
138 का०आ० 180 (अ) दिनांक 16 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमेंट (संरक्षण और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1974 का और आगे संशोधन करना ।
S.O.180(E), dated 16th April, 1975	Ministry of Industry & Civil Supplies	Further amendment of Cement (Conservation) and Regulation of use) Order, 1974 by the Central Govt.
139 का०आ० 181 (अ) दिनांक 18 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 का और आगे संशोधन करना ।
S.O. 181 (E), dated the 18th April, 1975	Ministry of Commerce	Further amendment of Export (Control) Order, 1968.

1	2	3	4
140	का०आ० 182 (अ) दिनांक 21 अप्रैल, 1975	वित्त मंत्रालय	बुधवार, 23 अप्रैल, 1975 भगवान महावीर के निर्वाण की 2500वीं जयन्ती का गुजरात राज्य में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में घोषित करना ।
	S.O. 182(E), dated the 21st April 1975	Ministry of Finance	Declaration of Wednesday the 23rd April 1975-2500th Anniversary of Lord Mahavira's Nirman as a Public holiday in the State of Gujarat.
141	का०आ० 183 (अ) दिनांक 22 अप्रैल, 1975	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अधिसूचना सं० 104-सीमाशुल्क, दिनांक 26 अगस्त, 1972 का और आगे संशोधन करना ।
	S.O. 183(E), dated the 22nd April 1975	Ministry of Finance	Further amendment to the Ministry of Finance (Department of Revenue) and Insurance No. 104-customs, dated the 26th August 1972.
142	का०आ० 184 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1975	अंतरिक्ष विभाग	भारत के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील, नियम, 1965 के अधिकारी नियुक्त करना ।
	S.O. 184 (E), dated the 25th April 1975	Department of Space.	Appointing and Disciplinary Authorities under CCS (CCA) Rules, 1965 by the President of India.
143	का०आ० 185 (अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मोटर कार (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1975 का और आगे संशोधन करना ।
	S.O. 185 (E), dated the25th April, 1975	Ministry of Industry a Civil Supplies	Further amendment of the Motor Cars (Distribution and Sale Control Order, 1959.
144	S.O. 186 (E), dated 25th April 1975	Ministry of Industry & Civil Supplies	Corrigendum to notification No. S.O. 147(C) dated 20th March, 1975.
145	का०आ० 187 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1975	भारत परिसीमन आयोग	परिसीमन आयोग द्वारा दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय तथा महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रकाशित किया जाना ।
	S.O. 187(E), dated the 28th April 1975	Delimitation Commission, India.	Publication of Delimitation of Parliamentary and Metropolitan Constiuencies in the Union Territory of Delhi.
146	का०आ० 188 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1 मई, 1975 से जहाजों द्वारा भारत के तटीय व्यापार में यात्रियों को ले जाने के लिए दरें नियत करना ।
	S.O. 188 (E) dated 28th April 1975	Ministry of Shipping & Transport	Fixation of Shipping rates w.e.f. 1st May 1975 for Ships-engaged in the Costing trade for the carriage of passengers.
147	का०आ० 189 (अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 का और आगे संशोधन करना ।
	S.O. 189 (E) dated 28th April 1975	Ministry of Commerce	Further amendment to the exports (Control) Order, 1968.
148	का०आ० 190 (अ) दिनांक 29 अप्रैल, 1975	श्रम मंत्रालय	कर्मचारियों के मासिक अभिदाय संचयन का गठित न्यासी-बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तरित कर देना ।
	S.O. 190(E) dated 29th April, 1975	Ministry of Labour	Transfer of monthly contribution of employees within fifteen days of the close to the month of the Board of Trustees.
	का०आ० 191 (अ) दिनांक 29 अप्रैल, 1975	श्रम मंत्रालय	भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों के अनुसार विनिहित करना ।
	S.O. 191(E) dated 29th April, 1975	Ministry of Labour	Investment in accordance with accumulations out of the Provident Fund Contribution, interest and other receipts.
149	का०आ० 192 (अ) दिनांक 29 अप्रैल, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और आगे संशोधन ।
	S.O. 192(E) dated 29th April, 1975	Ministry of Commerce	Further amendment to Exports (Control) Order, 1968.
150	का०आ० 193 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	विनिर्दिष्ट सारिका में कृषि के लिए बेचे जाने वाले बीजों की श्रेणी को नियमित करना ।
	S.O. 193(E) dated 30th April, 1975	Ministry of Agriculture and Irrigation	Expeditation to regulate quality of variety of seeds specified in the Table.
151	का०आ० 194 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 1975	गृह मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग को 9 अगस्त, 1975 तक बढ़ाना ।
	S.O. 194(E) dated 30th April, 1975	Ministry of Home Affairs	Extension of Commission of Inquiry upto 9th August 1975 by the Central Govt.
152	का०आ० 195 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	केन्द्रीय सरकार सीमेंट (संरक्षण और उपयोग का विनियम) आदेश, 1974 को 1 मई, 1975 से विखण्डित करना ।
	S.O. 195(E) dated 30th April, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies	Rescination of cement (Conservation and Regulation of Use) w.e.f. 1st May, 1975 by the Central Govt.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का० आ० 4460.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री शान्ति प्रसाद जैन एवं अन्यों (आर० सी० नं० 1/64/एफ०एस०/एस०यू०) के विरुद्ध 1972 का आपराधिक मामला संख्या 1/पी० में मुख्य मेट्रोपालिटन दण्डाधिकारी, बम्बई द्वारा दिनांक 18-7-75 को दिए गए आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण का तथा सैशन न्यायालय, बम्बई में मामले के विचारण का कार्यसंचालन करने के लिए बम्बई के एडवोकेट, सर्वश्री पी० पी० खम्बाट्टा और विजय आर० देसाई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है

[संख्या 225/52/75-ए०वी०डी०2]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 4460.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Sarvashri P. P. Khambatta and Vijay R. Desai, Advocates, Bombay, as Special Public Prosecutors for conducting the Revision filed by the State against the order dated the 18th July, 1975 of the Chief Metropolitan Magistrate, Bombay, in Criminal Case No. 1/P of 1972 and also the trial of the case in the Court of Sessions, Bombay, against Shanti Prasad Jain and others (RC. 1/64/FS/SU).

[No. 225/52/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० आ० 4461.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 235-सादात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पतिराम, ग्राम चकराजू पोस्ट सैदपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पतिराम को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/235/74(160)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4461.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Patiram, Village Chakraju, P.O. Saidpur, District Ghazipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 235-Sadat assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Patiram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/235/74(160)]

आदेश

का०आ० 4462.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 235-सादात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामजीत, ग्राम बिनवल, पो० रामपुर, माझा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामजीत को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/235/74(161)]

ORDER

S.O. 4462.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramjeet, Village Benwal, P.O. Rampur Majha, District Ghazipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 235-Sadat assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramjeet to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/235/74(161)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4463.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 109—राय बरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जमुना प्रसाद वकील, उत्तरी जहानाबाद, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जमुना प्रसाद वकील को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/109/74(165)]

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 4463.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jamuna Prasad Vakil, Uttari Jahanabad, District Rae Bareli Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 109-Rae Bareli assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jamuna Prasad Vakil to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/109/74(165)]

आदेश

का० आ० 4464.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 113—सलोन (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम लौटन, ग्राम नूरुद्दीन पुर, पोस्ट करहिया बाजार, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम लौटन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/113/74(168)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 4464.—Whereas te Election Commission is satisfied that Shri Ram Lautan, Vill. Nooruddinpur, P.O. Karhiya Bazar District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 113-Salon(SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Lautan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/113/74(168)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1975

आयकर

का० आ० 4465.—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड 43—ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 691 तारीख 30 जुलाई, 1974 का आंशिक उपान्तरण करते हुए अधिसूचना सं० 944 तारीख 23 जून, 1975 द्वारा यथा उपान्तरित अधिसूचना सं० 679 तारीख 20 जुलाई, 1974 की अनुसूची में उल्लिखित आयकर आयुक्त को कर वसूली आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तुरन्त प्रभावशील रूप में प्राधिकृत करती है ।

[सं० 1048 (फा० सं० 404/144/75-आई टी सी)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 21st August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4465.—In exercise of powers conferred by clause 43-B of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of notification No. 691 dated the 30th July, 1974, the Central Government hereby authorises the Commissioner of Income-tax, mentioned at Srl. No. 11 B of the Schedule to the Notification No. 679 dated the 20th July, 1974 as modified by notification No. 944 dated the 23rd June, 1975 to exercise the powers of Tax Recovery Commissioner with immediate effect.

[No. 1048 (F. No. 404/144/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का०आ० 4466.—अधिसूचना सं० 171 (फा० सं० 404/274/72-आई टी सी सी) तारीख 1 सितम्बर, 1972 और 190 (फा० सं० 404/274/72-आई टी सी सी) तारीख 18 सितम्बर, 1972 का आंशिक उपान्तरण करते हुए, उसके पैरा 1 में आने वाले क्रमशः सर्वश्री तेज प्रकाश और डी० एस० खोभा के नामों का लोप किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

[सं० 1052 (फा० सं० 404/63/75-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 23rd August, 1975.

S.O. 4466.—In partial modification of Notification Nos. 171 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated the 1st September, 1972 and 190 (F. No. 404/274/72-ITCC) dated the 18th September, 1972, the names of S/Shri Tej Prakash and D. S. Khobba appearing in para 1 thereof respectively are deleted.

2. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 1052 (F. No. 404/63/75-ITCC)]

का०आ० 4467.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी० आर० बैनेट को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख को श्री डी० आर० बैनेट कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

[सं० 1054 (फा० सं० 404/116/75-आई टी सी सी)]

S.O. 4467.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri D. R. Banet who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri D. R. Banet takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1054 (F. No. 404/116/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का०आ० 4468.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आर० के० श्रीवास्तव को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको श्री आर० के० श्रीवास्तव कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

[सं० 1058 (फा० सं० 404/104/75-आई टी सी सी)]

New Delhi, the 26th August, 1975

S.O. 4468.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorised Shri R. K. Srivastava who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri R. K. Srivastava takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1058 (F. No. 404/104/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1975

का०आ० 4469.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री अमित लाल पाल को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जिस तारीख को श्री अमित लाल पाल कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं ।

[सं० 1062 (फा० सं० 404/77/75-आई टी सी सी)]

वी० पी० मित्तल, उप-सचिव

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4469.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri Amit Lal Pal who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri Amit Lal Pal takes over as Tax Recovery Officer.

[No. 1062 (F. No. 404/77/75-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

आयकर

का०आ० 4470.—अधिसूचना सं० 521 (फा० सं० 203/12/73-आई टी ए आई I) तारीख 14 दिसम्बर, 1973 के अनुक्रम में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्थाओं विहित प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम 1962 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1975 से तीन वर्ष की और अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

1-4-75 से 27-7-75 तक

ऐग्री एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई ।

28-7-75 से 31-3-78 तक

ऐस्पी एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट फाउण्डेशन, मुम्बई ।

[सं० 1050 (फा० सं० 203/53/75-आई टी ए आई-1]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 22nd August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4470.—In continuation of notification No. 521 (F. No. 203/12/73-ITA.II), dated 14th December, 1973, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhawan, New Delhi the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a further period of three years with effect from 1st April, 1975.

INSTITUTION

From 1-4-1975 to 27-7-1975

Aspee Agricultural Research and Development Foundation Pvt. Ltd., Bombay.

From 28-7-75 to 31-3-78.

Aspee Agricultural Research and Development Foundation. Bombay.

[No. 1050/F. No. 203/53/75-ITA.II]

Sd/-

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1975

बीमा

का०आ० 4471.—साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) प्रथम संशोधन स्कीम, 1975 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य स्कीम कहा गया है), पैरा 2 में—

(क) खण्ड (iii) में, "अस्थायी पूर्णकालिक कर्मचारी" पद के पूर्व "31 दिसम्बर, 1972 को यथास्थित", पद अन्तःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (iv) और उसके नीचे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(iv) जो 1973 की जनवरी के प्रथम दिन या उसके पश्चात् भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी की सेवा में सम्मिलित हुए थे और इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनकी पुष्टि हो गई थी;

(v) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व निगम या उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियमित पूर्णकालिक अस्थाई सेवा में थे;

(vi) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पश्चात् निगम या उसकी समनुषंगियों में से किसी के द्वारा परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के रूप में नियुक्त किए जाएं ।"

3. मुख्य स्कीम के पैरा 3 के खण्ड (i) में "दफ्तरी" शब्द के पूर्व "ड्राइवर" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ।

4. मुख्य स्कीम के पैरा 4 में—

(i) उप-पैरा (1) में,—

(क) स्पष्टीकरण 1 में, "या खण्ड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "या खण्ड (iv) या खण्ड (v)" शब्द, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1क—इस पैरा और पैरा 5 तथा 6 के प्रयोजनों के लिए, पैरा 2 के खण्ड (iii) और (iv) तथा खण्ड (v) में निर्दिष्ट कर्मचारी की बाबत यह माना जाएगा मानो उसने नए वेतनमानों से शासित होने का विकल्प अपनाने का निश्चय किया था ।"

(ii) उप-पैरा (2) में—

(क) खण्ड (क) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि पैरा 2 के खण्ड (iii), (iv) और (v) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृन्द की दशा में, उपरोक्त अवधि से, सम्बन्धित कर्मचारी के निरन्तर सेवा में नियुक्ति की तारीख से आरम्भ या 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को आरम्भ, दोनों में से जो पश्चात्वर्ती हो, तथा 26 मई, 1974 को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत होगी";

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"जहां सुसंगत अवधि के दौरान कोई कर्मचारी ऐसे पद से भिन्न पद धारण कर रहा था जिस पर वह सामान्यतया नियोजित नहीं किया जाता था या अल्पकालिक प्रकृति का कोई भत्ता प्राप्त कर रहा था, वहां पैरा 4 और 6 के प्रयोजन के लिए, केवल वही वेतन और भत्ते (ऐसे अल्पकालिक भत्तों को अपवर्जित करके) गणना में लिए जाएंगे जो वह सामान्य पद में लेता;

(iii) उप-पैरा (3) में से खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा ।

5. मूल स्कीम के पैरा 5 में,—

(i) उप-पैरा 2 में, खण्ड (क) में—

(क) उपखण्ड (i) में, "और पर्यवेक्षी" शब्दों के स्थान पर "या पर्यवेक्षी और" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप-खण्ड (iii) में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "दक्षता" शब्द रखा जाएगा;

(ii) उप-पैरा (3) में, खण्ड (क) में, "वे सभी व्यक्ति जो आशुलिपिक के रूप में" शब्दों के स्थान पर, "उप-पैरा 4 के अधीन रहते हुए वे सभी व्यक्ति जो आशुलिपिक के रूप में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) उप-पैरा 4 में, "पैरा (2)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उप-पैरा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

6. मुख्य स्कीम के पैरा 6 में,—

(i) उप-पैरा (1) में—

(क) खण्ड (क) में—

(i) * * *

(ii) शब्द "कनिष्ठ", जिन दोनों स्थानों पर आया है, लोप किया जाएगा;

(iii) "इस अनुकल्प द्वारा अभिनिश्चित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "इस अनुकल्प के अधीन अभिनिश्चित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) * * *

(ग) * * *

(घ) टिप्पण 1 में, "को लेता" शब्दों के पूर्व "को अपने विद्यमान वेतनमान में लेता" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) टिप्पण 2 में "यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 के ठीक पूर्व किसी ऐसी कम्पनी में, जिसमें मंहगाई भत्ता का कोई निश्चित मान नहीं है, समेकित वेतन या भत्ता प्राप्त करता है, तो समेकित वेतन मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 को समेकित वेतन या भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो वह मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-पैरा (3) में और उप-पैरा (4) में "या उससे अधिक हो जाता है" शब्दों के पश्चात् "किन्तु श्रेणी की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाता" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-पैरा 5 में—

(क) "उक्त तारीख के" शब्द के स्थान पर "उक्त तारीख को" शब्द रखे जाएंगे और "ठीक पूर्व" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) "नकद में संदत्त लंच भत्ता" शब्दों के स्थान पर "सवारी भत्ता और, नकद में संदत्त, लंच भत्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु पैरा 2 के खण्ड (iv), (v) और (vi) में निर्दिष्ट कोई भी कर्मचारी वैयक्तिक वेतन का हकदार नहीं होगा";

(iv) उप-पैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) पैरा 2 के खण्ड (iv) और (v) में निर्दिष्ट कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवा में आमेलित किए जाने पर वेतन इस प्रकार अवधारित किया जाएगा मानों कि वह इस स्कीम के अधीन समुचित वेतनमान में नियुक्त किया गया था ।"

7. मुख्य स्कीम के पैरा 7 में, —

(i) उप-पैरा (1) में, "कर्मचारी को उसके वर्तमान वेतनमान में एक वृद्धि देने के पश्चात्" शब्दों के स्थान पर "कर्मचारी को उसके वर्तमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, देने के पश्चात् उसके वेतन के आधार पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप-पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण— "निरन्तर सेवा के बारह मास" से, असाधारण छुट्टी की अवधियों को अपवर्जित करते हुए, बारह मास के समतुल्य कार्य-अवधि अभिप्रेत है ।"

(iii) उप-पैरा (2) में—

(क) "पैरा 5" शब्द और अंक के स्थान पर "पैरा 6" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि" शब्दों के स्थान पर "वेतनवृद्धि" शब्द रखे जाएंगे ।

8. मुख्य स्कीम के पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. काम के घंटे—(1) पांच पूर्ण दिनों और एक आधे दिन वाले सप्ताह में काम के कुल घंटे —

(i) पर्यवेक्षी और लिपिकीय श्रेणियों के सभी कर्मचारियों के लिए, लंच के 45 मिनट छोड़कर, पैंतीस घंटे पन्द्रह मिनट होंगे ;

(ii) उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य अधीनस्थ कर्मचारि वृन्द के लिए, लंच के 45 मिनट छोड़कर, अड़तीस घंटे पन्द्रह मिनट होंगे ।

(2) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द, जैसे कि ड्राइवर, लिफ्टवाला, क्लीनर, पहरेदार, बिजली मिस्त्री, नलसाज और मालियों के लिए छह पूर्ण दिनों वाले सप्ताह में अड़तालीस घंटे होंगे ।

(3) उप-पैरा (1) और (2) में वर्णित सप्ताह में काम के अधिकतम घंटों की शर्त के अधीन रहते हुए प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक प्रत्येक कार्यालय और कर्मचारी के लिये दैनिक काम-घंटे उतने विनिर्दिष्ट कर सकेगा जितने कि वह आवश्यक समझे ।"

9. मुख्य स्कीम के पैरा 9 में "जहां ऐसे अवकाश दिनों की संख्या किसी वर्ष में" से आरम्भ और "शनिवार को पड़ने वाले अवकाश दिन पूर्ण अवकाश दिनों के रूप में माने जाएंगे" वाक्य से अन्त होने वाले सभी वाक्यों का लोप किया जाएगा ।

10. मुख्य स्कीम के पैरा 10 में, —

(1) उप-पैरा (1) में, खण्ड 1(छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

"(ज) असाधारण छुट्टी" ;

(2) उप-पैरा (2) में, "(घ) आकस्मिक छुट्टी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं किया जाएगा । इस शर्त के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अधीन किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में दी जा सकेगी", शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ङ) निम्नलिखित के सिवाय कोई भी छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के क्रम में या उसके साथ मंजूर नहीं की जा सकेगी :—

(i) परीक्षा छुट्टी के क्रम में या उसके साथ जोड़कर आकस्मिक छुट्टी तथा अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी,

(ii) बीमारी छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, परीक्षा छुट्टी, करन्तीन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के क्रम में या उनके साथ जोड़कर उपार्जित छुट्टी,

(iii) उपार्जित छुट्टी, बीमारी छुट्टी, करन्तीन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के क्रम में या उसके साथ जोड़ कर बीमारी छुट्टी,

(iv) उपार्जित छुट्टी, बीमारी छुट्टी, करन्तीन छुट्टी या असाधारण छुट्टी के क्रम में या उनके साथ जोड़ कर प्रसूति छुट्टी,

(v) आकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, उपार्जित छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, करन्तीन छुट्टी, या असाधारण छुट्टी के क्रम में या उनके साथ जोड़कर परीक्षा छुट्टी,

(vi) आकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, उपार्जित छुट्टी, बीमारी छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, परीक्षा छुट्टी या असाधारण छुट्टी के क्रम में या उनके साथ जोड़कर करन्तीन छुट्टी,

(vii) किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के क्रम में या उसके साथ जोड़कर असाधारण छुट्टी";

(3) उप-पैरा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) उपार्जित छुट्टी—(क) उपार्जित छुट्टी की संख्या कर्त्तव्य का एक बटा ग्यारह भाग के समतुल्य होगी।

स्पष्टीकरण — इस खण्ड में 'कर्त्तव्य' से अभिप्रेत है नियम या उसकी समनुषंगियों या दोनों की सेवा में व्यतीत अवधि, किन्तु इसके अन्तर्गत आकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, करन्तीन छुट्टी, परीक्षा छुट्टी और व्यवसाय संघ छुट्टी से भिन्न छुट्टी की अवधियां सम्मिलित नहीं होंगी।

(ख) उपार्जित छुट्टी की वह अवधि जो किसी कर्मचारी द्वारा संचित की जा सकेगी, एक सौ अस्सी दिन है और एक बार में अधिक से अधिक एक सौ बीस दिन की छुट्टी मंजूर की जा सकती है :

परन्तु कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पूर्व तैयारी के लिए छुट्टी के रूप में उसके लेखा मद्दे पूरी छुट्टी, किन्तु अधिक से अधिक एक सौ अस्सी दिन तक मंजूर की जा सकती है।

(ग) सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत कर्मचारी को सेवा के हित में उपार्जित छुट्टी से इन्कार किया जा सकता है और कर्मचारी को, उसकी मृत्यु होने की दशा में, उसके लेखा मद्दे शोध्य उपार्जित छुट्टी के लिए नकद में संदाय किया जा सकता है।

टिप्पणी 1—कर्मचारी को उपार्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय के परिणामस्वरूप शोध्य रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, कर्मचारी का सकल मासिक वेतन (आधारी वेतन और सभी भत्तों को मिलाकर किन्तु फार्यकरण भत्ता तथा प्रतिस्थानी भत्ता सम्मिलित न करते हुए) जितना कि वह, यथास्थिति, उसकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति की तारीख को हो, गणना में लिया जाएगा।

टिप्पण 2—कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को उसके लेखा मद्दे उपार्जित छुट्टी के बदले में नकद रकम दिये जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारी को जो रकम शोध्य हो वह उस व्यक्ति को संदत्त की जाएगी जिसे सम्बन्धित कर्मचारी की भविष्य निधि के अतिशोध देय हों।

(4) आकस्मिक छुट्टी – (क) कलैण्डर वर्ष में कर्मचारी को अधिक से अधिक पन्द्रह दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है और ऐसे वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा उपभोग न की गई आकस्मिक छुट्टी वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाएगी।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कर्मचारी को एक कलैण्डर वर्ष में 23½ दिनों और परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन घोषित छुट्टी के दिनों के बीच अन्तर के समतुल्य दिनों के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती है और ऐसी छुट्टी आगामी कलैण्डर वर्ष के दौरान ली जा सकती है। परन्तु यह कि ऐसी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी जो कि उपरोक्त आगामी कलैण्डर वर्ष के दौरान न ली जाए ऐसे वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाएगी।

(ग) उप-पैरा (2) के खण्ड (क) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी, के साथ जोड़ कर ली जा सकती है किन्तु एक समय में छह दिन से अधिक की आकस्मिक छुट्टी या अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी या दोनों मिलाकर नहीं ली जा सकती

(घ) आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी सामान्यतया सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के पश्चात् ही ली जा सकती है ; किन्तु एक दिन की आकस्मिक छुट्टी अनपेक्षित आपात की दशा में पूर्व मंजूरी के बिना ली जा सकती है :

परन्तु यह तब जबकि कार्यालय के प्रधान को उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें पूर्व मंजूरी नहीं ली जा सकी, शीघ्र सूचित कर दिया जाए।

(ङ) शनिवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन केवल पूर्वाह्न या अपरान्ह के लिए आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी ली जा सकती है और इस प्रकार ली गई छुट्टी की अवधि आधा दिन मानी जाएगी।

(च) शनिवार को ली गई आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी।

(4) उप-पैरा (6) में, परन्तुक में, "जिसके तीन जीवित बच्चे हों" शब्दों के स्थान पर "जिसके तीन और अधिक जीवित बच्चे हों" शब्द रखे जाएंगे ;

(5) उप-पैरा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"(10) असाधारण छुट्टी—(क) कर्मचारी को कुल सेवा के दौरान अधिक से अधिक छह मास की असाधारण छुट्टी तब मंजूर की जा सकती है जब कोई अन्य छुट्टी शोध्य न हो।

(ख) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा।

(ग) ऐसी छुट्टी पर व्यतीत अवधि वेतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाएगी।

(11) छुट्टी वेतन—उपार्जित छुट्टी, प्रसूति छुट्टी या करन्तीन छुट्टी के दौरान कर्मचारी उस वेतन के समतुल्य छुट्टी वेतन लेगा जो वह छुट्टी पर अग्रसर होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को प्राप्त कर रहा था।"।

11. मूल स्कीम के पैरा 11 में, "और मंहगाई भत्ते" शब्दों के स्थान पर "मंहगाई भत्ते और वैयक्तिक वेतन" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल स्कीम के पैरा 12 में, परन्तुक में, "ठीक अगले मास के प्रथम दिन को" शब्दों के स्थान पर "ठीक अगले मास के प्रथम दिन को पूर्वाह्न में" शब्द रखे जाएंगे।

13. पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"14. अतिकालिक भत्ता — (1) जब भी कार्यालय के कार्य के हित में यह आवश्यक समझा जाए, कर्मचारी के कार्य की प्रसामान्य अवधि से परे काम करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(2) जब किसी कर्मचारी से किसी दिन कार्य की प्रसामान्य अवधि के परे आधा घन्टे से अधिक समय करने की अपेक्षा की जाए तो उसे उसके कार्य की प्रसामान्य अवधि से परे की अवधि के लिए अतिकालिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(3) नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित कर्मचारियों के प्रवर्गों के लिए अतिकालिक भत्तों की दरें उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित की जाएंगी।

सारणी

कर्मचारियों के प्रवर्ग	संगणना की रीति
1	2
पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द	1. सप्ताह के दौरान अतिकालिक कार्य की अवधि जब उस सप्ताह के कार्य के प्रसामान्य अवधि के साथ जोड़ने पर बियालीस घंटे या कम हो तो अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 1-1/2 गुणा होगी ।
	2. सप्ताह में बयालीस घन्टे से अधिक के अतिकालिक कार्य की अवधि के लिए अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टे की दर का दो गुणा होगी ।
अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	1. सप्ताह के दौरान अतिकालिक कार्य की अवधि जब उस सप्ताह के कार्य के प्रसामान्य अवधि के साथ जोड़ने पर पैंतालीस घन्टे या कम हो तो अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 1-1/2 गुणा होगी ।
	2. सप्ताह में पैंतालीस घन्टे से अधिक के अतिकालिक कार्य की अवधि के लिए अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टे की दर का दो गुणा होगी ।
चालक (ड्राइवर) और निर्माण कर्मचारिवृन्द	1. सप्ताह के दौरान प्रथम सात घन्टे के अतिकालिक कार्य के लिए अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 1-1/2 गुणा होगी ।
	2. सप्ताह के दौरान प्रथम सात घन्टे से अधिक के अतिकालिक कार्य के घन्टों के लिए अतिकालिक भत्ते की दर मजदूरी की प्रति घन्टा दर का दो गुणा होगी ।

(4) अवकाश और रविवार के दिन किए गए अतिकालिक कार्य के लिए संदाय उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार पर अन्य दिनों के लिए :

परन्तु रविवार के दिन चार घन्टे या उससे अधिक के निरन्तर अतिकालिक कार्य के लिए अतिकालिक भत्ते के संदाय के अतिरिक्त एक प्रतिकरात्मक अवकाश भी दिया जाएगा ।

(5) निगम में या उसकी समनुषंगियों में से किसी में या क्षेत्र के, डिवीजन के और शाखा स्तर के अन्य कार्यालय में अतिकालिक भत्ते के संदाय की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी वे होंगे जो निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) सामान्यतया चालक (ड्राइवर) से भिन्न किसी भी कर्मचारी को एक कलेण्डर वर्ष में 90 घन्टे से अधिक अतिकाल में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा :

परन्तु प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक किन्हीं विशेष मामलों में कार्य की आभ्यावश्यकताओं के आधार पर इन उपबन्धों को शिथिल कर सकता है ।

टिप्पण 1. अतिकाल की अवधि निकटतम घन्टे में पूर्णांकित की जाएगी ।

टिप्पण 2. सप्ताह की गणना रविवार से शनिवार तक की जाएगी ।

टिप्पण 3 मजदूरी की प्रति घन्टा दर वह होगी जो मास के सकल वेतन को (आधारी वेतन, मंहगाई भत्ता, अर्हता वेतन, कार्यकरण भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, पहाड़ी आस्थान भत्ता, वैयक्तिक वेतन और प्रतिस्थानी भत्ते को सम्मिलित करके) उस मास के कार्य के प्रसामान्य घन्टों से विभाजित करके प्राप्त हो ।

14. मुख्य स्कीम की प्रथम अनुसूची में, "अर्हता वेतन" से सम्बन्धित मद IV के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

" IV अर्हता वेतन :

कर्मचारियों को एक मासिक भत्ता, जिसे अर्हता वेतन कहा जाएगा, दिया जाएगा या निम्नलिखित आधार पर वेतन-वृद्धियां दी जाएंगी, अर्थात् :—

(1) अस्नातक सहायकों को, जो सेवा में 31 दिसम्बर, 1972 को पुष्ट किए गए थे और जो 31 दिसम्बर, 1977 से पूर्व स्नातक के रूप में अर्हित हो जाएं, उनके वेतनमान में, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से, दो वेतन-वृद्धियां दी जाएंगी ।

(2) अस्नातक सहायकों को, जो 31 दिसम्बर, 1972 को अस्थायी सेवा में थे और 31 दिसम्बर, 1977 से पूर्व स्नातक के रूप में अर्हित हो, उनके वेतनमान में, सेवा में उनकी पुष्टि की तारीख से या परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख दोनों में से जो पश्चात्वर्ती हो, दो वेतन-वृद्धियां दी जाएंगी ।

(3) 31 दिसम्बर, 1972 को सेवागत स्नातक सहायकों को, यदि आवश्यक हो तो, उनके आधारी वेतन में, सेवा में उनकी पुष्टि की तारीख से या 1 जनवरी, 1973 से, दोनों में से जो पश्चात्वर्ती हो, वेतनवृद्धि अनुज्ञात की जा सकती है ताकि उनके आधारी वेतनों को सहायक के वेतनमान में तृतीय आयाम के स्तर तक लिया जा सके ।

परन्तु यह तब जब कि सम्बन्धित स्नातक सहायक को उच्चतर आरम्भिक वेतन या अग्रिम वेतनवृद्धियां स्नातक होने के पूर्व, बीमाकर्ता के साथ सेवा की अवधि में किसी समय, अनुज्ञात न की गई हों

(4) सहायक के प्रवर्ग में या समतुल्य पदों पर 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उनकी श्रेणी में दो वेतनवृद्धियां —

(क) सेवा में उनकी पुष्टि की तारीख से दी जाएंगी यदि वे स्नातक के रूप में सेवा में सम्मिलित हुए हों अथवा पुष्टि के पूर्व स्नातक के रूप में अर्हित हो जाते हैं;

(ख) परिणामों के प्रकाशन की तारीख से दी जाएंगी यदि वे सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, किन्तु सेवा में पुष्टि के पश्चात्, स्नातक के रूप में अर्हित हो जाते हैं ।

(5) उस संपुष्ट कर्मचारी को जो निम्नलिखित परीक्षा में अर्हित हो जाता है या अर्हता प्राप्त कर चुका है, परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख से या 27 मई, 1974 से, दोनों में से जो पश्चात्वर्ती हो, नीचे उल्लिखित के अनुसार अर्हता वेतन की रकम संघत्त की जाएगी :

परन्तु उस एक से अधिक अर्हता वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा ।

परीक्षा	प्रति मास अर्हता वेतन
फैडरेशन आफ इण्योरेंस इन्स्टीट्यूट या चार्टर्ड इंण्योरेंस इन्स्टीट्यूट	
(i) लाइसैंशियेट	15 रु० जो केवल सहायक या समतुल्य या निम्नतर पद के धारक को देय है ।
(ii) एसोशिएटशिप पूरी करना	25 रु० जो वरिष्ठ सहायक या समतुल्य या निम्नतर पदों के धारक को देय है ।
(iii) फैलोशिप पूरी करना	50 रुपए
इन्स्टीट्यूट आफ एक्चुरीज :	
(iv) कोई तीन विषय	25 रु०
(v) कोई सात विषय	40 रु०
(vi) फैलोशिप पूरी करना	60 रु०
इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउन्टैन्स या इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउण्टैन्ट्स ।:	
(vii) इन्टरमीडिएट पूरी करना	25 रु०
(viii) एसोशिएटशिप या फैलोशिप पूरी करना	50 रु०

(6) स्नातक होने पर अर्हता वेतन या वेतनवृद्धियों की मंजूरी का सम्बन्धित व्यक्ति की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(7) जहां किसी कर्मचारी को पहले ही अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई हो या कोई अन्य आवर्ती धनीय फायदा किसी बीमा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के कारण पहुंचाया गया हो वहां अर्हता वेतन की रकम उचित रूप से कम कर दी जाएगी या पहले से प्राप्त किए गए फायदे के परिमाण के आधार पर पूरी तरह अनुज्ञेय होगी ।

उदाहरण :

सहायक को फैडरेशन आफ इण्योरेंस इन्स्टीट्यूट की एसोशिएटशिप परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उप-पैरा (5) की शर्त के अनुसार अनुज्ञेय 25 रु० प्रति मास के स्थान पर केवल 5 रु० प्रति मास का अर्हता वेतन मिलेगा यदि इस परीक्षा के लिए प्राप्त सभी अग्रिम वेतनवृद्धियों का कुल धनीय मूल्य 20 रु० प्रति मास हो और उसे कोई भी अर्हता वेतन नहीं मिलेगा यदि पहले ही प्राप्त अग्रिम वेतनवृद्धियों का कुल धनीय मूल्य 25 रु० प्रति मास हो ।

15. मुख्य स्कीम की द्वितीय अनुसूची में, "यात्रा भत्ता" शीर्षक के नीचे, "रेल द्वारा यात्रा" से सम्बन्धित मद (1) और उसके अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) रेल द्वारा यात्रा :

(i) 340 रु० तथा अधिक आधारी वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	प्रथम श्रेणी
(ii) 340 रु० से कम आधारी वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी	द्वितीय श्रेणी (नई) और रात्रि यात्रा के लिए शायिका
(iii) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द	द्वितीय श्रेणी (नई) और रात्रि यात्रा के लिए शायिका" ।

[फा० सं० 65(8) इंश्यो III/15-क/74)]

ग० ह० दामले, बीमा नियंत्रक और पदेन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4472—केन्द्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा नियम, 1939 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है । जैसाकि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है । इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप

1. इन नियमों का नाम बीमा (संशोधन) नियम, 1975 है ।

2. बीमा नियम, 1939 में, नियम 2 में, खण्ड (iv), (v) और (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(iv) 'कलकत्ता क्षेत्र' से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें आसाम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य और नागालैण्ड राज्य का ट्यूनसांग जिला तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र समाविष्ट है;

(v) 'दिल्ली क्षेत्र' से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं;

(vi) "मद्रास क्षेत्र" से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं; और

[सं० 51(1)बीमा-I/75]

आर० के० महाजन, निदेशक ।

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4472.—The following draft of certain rules further to amend the Insurance Rules, 1939, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), is published as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration by the Central Government after the expiry of 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any obections or suggestions which may be received from any person with respect to the draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT

1. These rules may be called the Insurance (Amendment) Rules, 1975.

2. In the Insurance Rules, 1939, in rule 2, for clauses (iv), (v) and (vi) the following clauses shall be substituted, namely:—

"(iv) 'Calcutta area' means the area comprising the states of Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya,

Orissa, West Bengal, Sikkim and Tripura and the Tuensang district in the state of Nagaland and the Union territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and Andaman and Nicobar Islands;

(v) 'Delhi area' means the area comprising the states of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union territories of Delhi and Chandigarh;

(vi) 'Madras area' means the area comprising the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and the Union territories of Pondicherry and Lakshadweep; and

[F. No. 51(1) INS. I/75]

R. K. MAHAJAN, Director

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4473.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ० सं० 673/39/75-उत्पाद-viii, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री किलुरु मुहम्मद, 198, अंगप्पा नायकर स्ट्रीट, मद्रास-1 को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, मद्रास केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए हैं;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य मैट्रोपालिटन मिजस्ट्रेट एगमोरे, मद्रास-600008 के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/39/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1975

S.O. 4473.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/39/75-Cus. VIII dated the 7th July, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri Kiluru Mohamed, 198, Angappa Naicker Street, Madras-1 be detained and kept in custody in the Madras Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Metropolitan Magistrate, Egmore, Madras-600008 within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/39/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4474.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ० सं० 673/41/75-उत्पाद-VIII, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एस०ओ० हाजा मोहिनुद्दीन सुपुत्र श्री एस० उथामन, 3/58, वैस्ट स्ट्रीट, पनाइकुलम, रामनाद जिला (तमिलनाडु) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, मद्रास केन्द्रीय कारागार मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए हैं;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई, (तमिलनाडु) के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/41/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4474.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/41/75-Cus. VIII dated the 7th July, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri S. O. Haja Mohinuddin s/o Shri S. Uthaman, 3/58, West Street, Pannaikulam, Ramnad Distt. (Tamil Nadu) be detained and kept in custody in the Madras Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1) (b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate, Ramanathapuram @ Devakottai, (Tamil Nadu) within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/41/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4475.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ० सं० 673/44/75-उत्पाद-VIII, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एम० वाई० हाजा मोहतीन सुपुत्र माहियामारीकर, सं० 2, कोहलक्का वाडी अहमद नीना लेन, नागोर नागापट्टीनम तालुक, तंजोर जिला (तमिलनाडु) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तंजावुर उर्फ कुम्बाकोनम (तमिलनाडु) के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/44/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4475.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/44/75-Cus. VIII dated the 7th July, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri M. Y. Haja Moideen son on Mahiyamaricar, No. 2, Koilakka Vadi Ahmed Nina Lane, Nagore, Nagapatinam Taluk, Tanjore District (Tamil Nadu) be detained and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate, Thanjavur. @ Kumbakonam (Tamil Nadu) within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/44/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4476.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/55/75-उत्पाद-VIII, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एच० ओबायदुल हक, पुत्र एम० हबीब मुहम्मद, 64, पेरिया पालीवासल स्ट्रीट, ग्राम आयनगुडी, चिदाबरम तालुक, साउथ अरकोट जिला (तमिलनाडु) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, मद्रास केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2 केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुडालोरे एन० टी० साऊथ अरकोट जिला (तमिलनाडु) के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/55/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4476.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/55/75-Cus. VIII dated the 7th July, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri H. Obaidul Huq, s/o M. Habeeb Mohamed, 64, Peria Pallivasal Street, Ayangudi Village, Chindambaram Taluk, South Arcot District, (Tamil Nadu) be detained and kept in custody in the Madras Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate, Cuddalore N.T. South Arcot Distt. (Tamil Nadu) within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/55/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4477.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/62/75-उत्पाद-VIII, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री मुहम्मद मुस्तफा पुत्र ए० नाला इब्राहीम, 10 कीराडकरा स्ट्रीट, वेलीपटनम, रामनाथपुरम (तमिलनाडु) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाइ (तमिलनाडु) के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/62/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4477.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/62/75-Cus. VIII dated the 7th July, 1975 under sec. tion 3(1) ibid directing that Shri Mohamed Mustafa S/o A. Nalla Ibrahim, 40 Keerakara Street, Velipatnam, Ramanathapuram (Tamil Nadu) be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct that aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate, Ramanathapuram @ Devakottai (Tamil Nadu) within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/62/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4478.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/65/75-VIII, तारीख 10 जुलाई, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री पपु किशनचन्द मेलवानी सुपुत्र किशन चन्द पो० मेलवानी, निवासी ग्रीन होटल, पुतली बावली, हैदराबाद को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, हैदराबाद में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिस आयुक्त, हैदराबाद के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/65/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4478.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/65/75-Cus. VIII dated the 10th July, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri Papu Kishinchand Melwani S/o Kishinchand P. Melwani, residing at Green Hotel, Pulli Bowli, Hyderabad, be detained and kept in custody in the Central Jail, Hyderabad with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe tha the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Hyderabad within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/65/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4479.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/113/75-उत्पाद-VIII, तारीख 5 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री पोथीराकाथू युसुफ हाजी, पोथीराकाथू हाउस, मातूल पो० आ०, कन्नानूर जिला (केरल) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह पुलिस अधीक्षक, कन्नानौर, केरल के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/113/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4479.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/113/75-Cus. VIII dated the 5th August, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri Pothirakathu Yusuf Haji Pothirakathu House, Mattool P.O. Cannanore District (Kerala) be detaind and kept in custody in the Central Prison, with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Superintendent of Police Cannanore, Kerala within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/113/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4480.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ० सं० 673/125/75-उत्पाद-VIII, तारीख 5 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया गया था कि श्री जे० दिनकरन, सुपुत्र जगन्नाथ पिल्ले, थिरुप्पल्लानी, रामनाद डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई, तमिलनाडु के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/125/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4480.—Whereas the Joint Secretary to he Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/125/75-Cus. VIII dated 5-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri J. Dinakaran, S/o Jagannatha Jillai, Thiruppullani, Ramnad District, Tamil Nadu be detained and

kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate Ramanathapuram, @ Devakottai. Tamil Nadu within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/125/75-Cus.-VIII]

आदेश

का० आ० 4481.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/129/75-उत्पाद-VIII, तारीख 5 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एच० एम० आबिद हुसैन, सुपुत्र एच० मुहम्मद हनीफ साहिब, निवासी दूसरी मंजिल नं० 43, मूकेर नालामुथु स्ट्रीट, मद्रास-1 को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाये ; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, एगमोर, मद्रास के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/129/75 उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4481.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/129/75-Cus. VIII dated the 5th August, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri H. M. Abidh Hussain s/o H. Mohamed Hanif Sahib, residing at 2nd Floor, No. 43, Mooker Nallamuthu Street, Madras-1 be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Metropolitan Magistrate, Egmore Madras within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/129/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4482.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/137/75-उत्पाद-VIII, तारीख 5 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री ए० मुहम्मद सुलतान सुपुत्र अब्दुल कादर, एस० कोडीकुलम, चेतियारकुडी (वाया) परमकुडी तालुक, रामनाद डिस्ट्रिक्ट को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाइ, तमिलनाडु, के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/137/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4482.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/137/75-Cus. VIII dated 5-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri A. Mohamed Sultan, S/o Abdul Kadar, S. Kodikulam, Chattirakudi (via) Paramakudi Taluk, Ramnad Distt. be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to apear before the Chief Judicial Magistrate, Ramanathapuram @ Devakottai, Tamil Nadu within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/137/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4483.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/148/75-उत्पाद-VIII, तारीख 11 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री पी० षन्मुगम सुपुत्र पैरियाना पिल्ले, प्रोप्राइटर मैसर्स षन्मुगा ट्रेडिंग कारपोरेशन, नं० 61, नार्थ चंदर स्ट्रीट, त्रिची, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्रिची, तमिलनाडु, के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/146/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4483.—Wheras te Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/146/75-Cus. VIII dated 11-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri [illegible] s/o Perianna Pillai, Prop. M/s. Shanmuga [illegible] No. 61, North Andar St., Trichy, be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Gentral Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate Trichy, Tamil Nadu within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[F. No. 673/146/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4484.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/151/75–उत्पाद- VIII, तारीख 11 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री के० एम० के० सोमसुन्दरम चेत्तियार सुपुत्र कुमारप्पा चेत्तियार, अमरावतीपुदूर, रामनाद डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए, और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई, तमिलनाडु के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/151/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4484.—Whereas the Joint Secretary to Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/151/75-Cus. VIII dated 11-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri K. M. K. Somasundaram Chettiar s/o Kumarappa Chettiar, Amaravathipudur, Ramnad Dist., Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct that aforesaid person to appear before the Chief Judicial Magistrate Ramanathapuram @ Devakottai, Tamil Nadu with in 7 days of the publication of this order in official gazette.

[No. F. 673/151/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4485.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/161/75–उत्पाद–VIII, तारीख 11 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एन० एम० गनी, सैयद उम्मा मंजिल, लार्डस स्ट्रीट, किलाकराई, रामनाद डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए; और

2. केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके, फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की धारा 7 (1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई, तमिलनाडु के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो।

[सं० 673/161/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4485.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/161/75-Cus. VIII dated 11-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri N. M. Gani, Syed Umma Manzil, Lords Street, Kilakarai, Ramnad District, Tamil Nadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Chief Judicial Mafiistrate, Ramanathapuram @Devakottai, Tamil Nadu within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[No. F. 673/161/75 Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4486.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/189/75-उत्पाद-VIII तारीख 11 अगस्त 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एम० टी० पी० अब्दुल्ला, सुपुत्र के० पी० मूसा, कूलोरी हाउस, त्रिकरीपुर, जिला कन्नानूर, केरल राज्य को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से केन्द्रीय कारागार, तिवेन्द्रम में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और

2. केन्द्रीय सरकार के यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1)(ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि पुलिस अधीक्षक कन्नानूर केरल के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/189/75-उत्पाद VIII]

ORDER

S.O. 4486.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/189/75-Cus. VIII dated 11-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri M.T.P. Abdulla s/o K. P. Moosa, Koolori House, Trikaripur, Cannanore Dt., Kerala State be detained and kept in custody in the Central Prison, Trivandrum with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Superintendent of Police, Cannanore, Kerala within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[No. F. 673/189/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4487.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/210/75 उत्पाद-VIII तारीख 18 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री भगवानदास एस० चेतनाणी, सुपुत्र शोभराज चेतनाणी, 571, सिल्वर क्वीन, एलजे II क्रास रोड, महीम मुम्बई को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, मुम्बई में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन न हो सके फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त व्यक्ति निदेश करती है कि पुलिस आयुक्त बृहत्तर मुम्बई, मुम्बई के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन को सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/210/75-उत्पाद-VIII]

ORDER

S.O. 4487.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/210/75-Cus. VIII da'ed the 18th August, 1975 under section 3(1) ibid directing that Shri Bhagwandas S. Chetnani, S/o Shobraj Chetnani, 571 Silver Queen, L/J II Cross Road, Mahim, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay, Bombay within 7 days of the publication of this order in official gazette.

[No. F. 673/210/75-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 4488.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन आदेश एफ सं० 673/285/75-उत्पाद-VIII, तारीख 19 अगस्त, 1975 को जारी किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री ईश्वर किशनचन्द मेलवानी सुपुत्र किशनचन्द पी० मेलवानी, द्वारा ग्रीन होटल, बोर्डिंग एण्ड लाजिंग, पुतली बावली, हैदराबाद, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, केन्द्रीय कारागार, हैदराबाद में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि आदेश का निष्पादन हो सके फरार हो गया है या स्वयं को छिपाए हुए है ;

3. अतः केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 7(1) (ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि पुलिस आयुक्त, हैदराबाद के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो ।

[सं० 673/285/75-उत्पाद-VIII]

पी० सी० जैन, उप-सचिव

ORDER

S.O. 4488.—Whereas the Joint Secretary to te Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 673/285/75-Cus. VIII dated 19-8-1975 under section 3(1) ibid directing that Shri Iswar Kishinchand Melwani, s/o Kishinchand P. Melwani, c/o Green Hotel, Boarding and Lodging, Putli Bowli, Hyderabad be detained and kept in custody in the Central Prison, Hyderabad with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed.

3. The Central Government in exercise of powers under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct the foresaid person to appear before the Commissioner of Police, Hyderabad within 7 days of the publication of this order in official Gazette.

[No. F. 673/285/75-Cus. VIII]

P. C. JAIN, Dy. Secy.

भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

का० आ० 4489.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में सितम्बर 1975 के दिनांक 19 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा हुए विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में			सोने का सिक्का और बुलियन:—		
रखे हुए नोट	42,23,88,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
संचलन में नोट	6228,42,50,000		विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,53,000
जारी किये गये कुल नोट		6270,66,38,000	रुपये का सिक्का		16,00,28,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5950,39,57,000
			देशी विनियम बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		..
कुल देयताएं		6270,66,38,000	कुल आस्तियां		6270,66,38,000

दिनांक : 24 सितम्बर 1975

के० आर० पुरी, गवर्नर

19 सितम्बर 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	42,23,88,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,99,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,62,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	55,59,60,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	1157,75,96,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	671,42,83,000
जमा राशियां:—		निवेश**	284,63,86,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम:—	
(i) केन्द्रीय सरकार	59,75,05,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	10,90,12,000	(ii) राज्य सरकारों को@	79,15,07,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	557,76,80,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	137,52,00,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,70,63,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को‡	322,28,46,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,48,70,000	(iii) दूसरों को	12,07,86,000
(iv) अन्य बैंक	67,04,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,63,82,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,54,13,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित निगम को	87,20,00,000
(ग) अन्य	1170,25,00,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	93,41,32,000
देय बिल	147,14,11,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	

	रुपये		रुपये
अन्य देयताएँ	720,69,98,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	324,99,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/ डिबेंचरों में निवेश	
		अन्य आस्तियां	342,21,34,000
	3703,37,43,000		3703,37,43,000

*नकदी, आयधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

©राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 41,07,00,000 रुपये शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

के० आर० पुरी, गवर्नर

दिनांक : 24 सितम्बर, 1975

[सं० एफ० 10(1)/75-बी० ओ० I]

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 26th September, 1975

S.O. 4489.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 19th day of September, 1975.

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	42,23,88,000		Gold Coin and Bullion :— (a) Held in India	182,52,56,000	
Notes in Circulation	6228,42,50,000		(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	121,73,97,000	
Total notes issued		6270,66,38,000			
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		16,00,28,000
			Government of India Rupee Securities		5950,39,57,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6270,66,38,000	Total Assets		6270,66,38,000

Dated the 24th day of September 1975

K.R. PURI, Governor.
C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 19th September, 1975.

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	42,23,88,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	2,99,0000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	Small Coin	4,62,000
		Bills purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Stablisation) Fund	140,00,00,000	(a) Internal	55,59,60,000
National Industrial (Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	1157,75,96,000
Deposit :—		Balances Held Abroad*	671,42,83,000
		Investments**	284,63,86000
(a) Government		Loans and Advances to :—	
(i) Central Governments	59,75,05,000	(i) Central Government	..
(ii) State Governments	10,90,12,000	(ii) State Governments@	79,15,07,000
(b) Banks		Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	557,76,80,000	(i) Scheduled Commercial Banks+	137,52,00,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,70,63,000	(ii) State Co-operative Banks++	322,28,46,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,48,70,000	(iii) Others	12,07,86,000
(iv) Other Banks	67,04,000		

(c) Others	1170,25,00,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
Bills Payable	147,14,11,000	(a) Loans and Advances to :—	
Other Liabilities	720,69,98,000	(i) State Governments	69,63,82,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,54,13,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	93,41,32,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	324,99,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	..
		Other Assets	342,21,34,000
RUPEES	3703,37,43,000	RUPEES	3703,37,43,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including Temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 41,07,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act.

++Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 24th day of September, 1975.

K.R. PURI, Governor

[No. F.10(1)/75-BO I]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 4490.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री द०म० मुकथनकर के स्थान पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली के निदेशक श्री ल० द० कटारिया को एतद्द्वारा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9(2)/75-बी०ओ० I(1)]

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4490.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management ad Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri L. D. Kataria, Director, Department of Banking Ministry of Finance, New Delhi as a Director of United Commercial Bank, *vice* Shri D. M. Sukthankar.

[No. F. 9/2/75-BO. I(1)]

का०आ० 4491.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री द०म० मुकथनकर के स्थान पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग नई दिल्ली के निदेशक, श्री ल० द० कटारिया को एतद्द्वारा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ 9(2)/75-बी०ओ०/(2)]

S.O. 4491.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri L. D. Kataria, Director, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of United Bank of India, *vice* Shri D. M. Sukthankar.

[No. F. 9/2/75-BO. I(2)]

का०आ० 4492.—राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री द० मं० मुकथनकर के स्थान पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली के उप सचिव श्री वी० के० शंगलू को एतद्द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेश के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ 9(2)/75 बी० ओ० I(3)]

ल० अ० मीरचंदानी अवर सचिव

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4492.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Shunglu, Deputy Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Bank of Maharashtra, *vice* Shri D. M. Sukthankar.

[No. F. 9/2/75-BO. I(3)]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

का० आ० 4493.—बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 14 अक्तूबर, 1972 के भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 उपखंड (ii) के पृष्ठ 4242 पर प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग की 12 जुलाई, 1972 की अधिसूचना सं० एफ० 8/2/72-ए०सी० 939 के सिलसिले में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 और 24 के उपबन्ध किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम के अलावा सहकारी समितियों का वित्त पोषण करने वाले किसी राज्य सहकारी बैंक पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि उक्त धाराओं के अनुसार उक्त सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि इन सहकारी बैंकों द्वारा, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा समितियों के रजिस्ट्रीकरण की अन्य अधिनियमितियों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत तथा छोटे किसानों और सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के विकास में लगी हुई समितियों से लिये गये ऋणों के कारण उद्भूत दायित्वों के संबंध में उक्त धाराओं में उल्लिखित क्रमशः नकदी प्रारक्षित का प्रतिशत तथा न्यूनतम परि सम्पत्तियाँ अपने पास रखे रहेंगे।

[सं० एफ० 8/9-75 ए०सी०]

ह० के० गुहा, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 1975

S.O. 4493.—In exercise of he powers conferred by section 53 read with section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Banking No. F. 8/2/772-AC-939, dated 12th July, 1972 published at page 4242 in Part II of Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated 14th October 1972, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sections 18 and 24 of the said Act shall not, for a further period of five years from 14th October, 1975, aply to any central co-operative bank or to any State co-operative bank which finances co-operative societies otherwise than through central co-operative banks, in so far as the said sections require such co-operative bank to maintain the percentage of cash reserve and a minimum of assets respectively mentioned therein in respect of the liabilities arising out of the loans availed of by the said co-operative banks from societies registered under the Societies Regulation Act, 1860, (21 of 1860) or under any other similar enactment for the registration of societies, and engaged in the development of small farmers and marginal farmers and agricultural labourers.

[No. F. 8/9/75-AC]

H. K. GUHA, Under Secy.

का०आ० 4494.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री दिलीप मुखर्जी को गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और दिनांक 2 अक्तूबर, 1975 से आरम्भ होकर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को, उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसके दौरान श्री दिलीप मुखर्जी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ 4-11/75-ए०सी०-1]

New Delhi, the 2nd October, 1975

S.O. 4494.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri Dilip Mukherjee as the Chairman of the Gaur Gramin Bank, Malda and specifies the period commencing on the 2nd October, 1975 and ending with 31st March, 1976, as the period for which the said Shri Dilip Mukherjee shall hold office as such chairman.

[No. F. 4-11/75-AC-I]

का०आ० 4495.—क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस०एल० जैन को जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 2 अक्तूबर, 1975 से आरम्भ हो कर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसके दौरान श्री एस० एल० जैन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 4-12/75-ए०सी०-1]

S.O. 4495.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri S. L. Jain as the Chairman of the Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur and specifies the period commencing on the 2nd October, 1975 and ending with 31st March, 1976, as the period for which the said Shri S. L. Jain shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-12/75-AC-I]

का०आ० 4496.—क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री के० डी० अग्रवाल को गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 2 अक्तूबर, 1975 से आरम्भ हो कर 31 मार्च 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसके दौरान श्री के० डी० अग्रवाल अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 4-13/75-ए०सी०-1]

S.O. 4496.—In exercise of the powers confered by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri K. D. Agarwal as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur and specifies the period commencing on the 2nd October, 1975 and ending with the 31st March, 1976, as the period for which the said Shri K. D. Agarwal shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-13/75-AC-I]

का०आ० 4497.—क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० पी० मेहरा को हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 2 अक्तूबर, 1975 से आरम्भ हो कर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को, उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसके दौरान श्री एस० पी० मेहरा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 4-14/75-ए० सी०-1]

S.O. 4497.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri S. P. Mehra as the Chairman of the Haryana Keshetriya Gramin Banks, Bhiwani and specifies the period commencing on the 2nd October, 1975 and ending with the 31st March, 1976, as the period for which the said Shri S. P. Mehra shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-14/75-AC-I]

का०आ० 4498.—क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश 1975 (1975 का 13) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री आर० के० गर्ग को प्रथम बैंक मुरादाबाद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 2 अक्तूबर, 1975 से आरम्भ हो कर 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि को, उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसके दौरान श्री आर० के० गर्ग अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 4-15/75-ए सी-1]
अमल कुमार दत्त, संयुक्त सचिव

S.O. 4498.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordinance, 1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri R. K. Garg as the Chairman of the Prathama Bank, Moradabad and specifies the period commencing on the 2nd October, 1975 and ending with the 31st March, 1976, as the period for which the said Shri R. K. Garg shall hold office as such Chairman.

[No. F. 4-15/75-AC-I]
A. K. DUTT, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4499.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पाइप फिटिंगें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होनी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

अतः, अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति, उसे इस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद, 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर', 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि पाइप फिटिंगें निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगी;

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को जो इस आदेश के उपाबन्ध-II में दिया गया है, पाइप फिटिंग निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1975 के प्रारूप के अनुसार, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी पाइप फिटिंग पर लागू किया जाएगा;

(3) उन विनिर्देशों के जिन्हें इस आदेश के उपाबन्ध-III में दिए गए न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए, निर्यातकर्ता द्वारा पाइप फिटिंगों के लिए निर्यात संविदा के करार पाए गए विनिर्देश घोषित किया गया है, पाइप फिटिंग के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी किन्हीं पाइप फिटिंगों के निर्यात का तब तक प्रतिषेध करना, जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि पाइप फिटिंगें क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करती हैं और निर्यात योग्य हैं।

3. इस आदेश की कोई भी बात पाइप फिटिंगों के नमूनों के भू-मार्ग, समुद्रमार्ग या वायु मार्ग द्वारा भावी क्रेताओं को उस निर्यात को लागू नहीं होगी, जिसका पोत तक निःशुल्क मूल्य 125 रु० से अधिक न हो।

4. इस आदेश में 'पाइप फिटिंगों से इस्पात या आघातवर्धनीय ढलवां लोहे से विनिर्मित फिटिंगें अभिप्रेत हैं। कुछ सामान्य फिटिंगें इस आदेश के उपाबन्ध-I में दी गई हैं।

उपाबन्ध-I

1. साकेट
2. पुरजे
3. लम्बे पेंच (योजक)
4. मोड़
5. स्प्रिंग
6. वापसी मोड़
7. निपल
8. एलबो
9. टी
10. क्रास
11. वार्ड पुरजे
12. कैप
13. प्लग
14. बैकडिबर्गी
15. यूनियन
16. बुशें
17. रिड्यूसर

उपाबन्ध-II

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : इन नियमों का नाम पाइप फिटिंग निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1975 है।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है;

(ग) 'पाइप फिटिंग' से इस्पात या आघातवर्धनीय ढलवां लोहे से विनिर्मित फिटिंग अभिप्रेत हैं। कुछ सामान्य फिटिंग उपाबन्ध 1 में दी गई हैं।

3. निरीक्षण का आधार: निर्यात के लिए पाइप फिटिंगों का निरीक्षण, परेषण के तैयार होने पर, यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया: (1) पाइप फिटिंगों का निर्यात करने का आशय रखने वाला कोई निर्यातकर्ता ऐसा करने के लिए अपने आशय की लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐसी सूचना के साथ, निर्यात-संविदा में अनुबद्ध विनिर्देशों की घोषणा सभी तकनीकी विशेषताएं बताते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक को देगा जिससे कि वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके। वह साथ ही निरीक्षण की ऐसी सूचना की एक प्रति अभिकरण के कार्यालय के निकटतम निर्यात निरीक्षण परिषद् कार्यालय को भेजेगा। परिषद के पते निम्न प्रकार हैं :—

प्रधान कार्यालय . . निर्यात निरीक्षण परिषद्,
'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर'
14/1-बी, एज़रा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल,
कलकत्ता-700001।

क्षेत्रीय कार्यालय : . . 1. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
अमन चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल,
113, महर्षि कर्वे रोड,
मुम्बई-400004।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद्,
मनोहर बिल्डिंग
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम, कोचीन-11।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, पोत लदान की अनुसूचित तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पूर्व अभिकरण तथा परिषद् के कार्यालय में पहुंचेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम 3 तथा परिषद द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार, यदि कोई हों, पाइप फिटिंगों का निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण तुरन्त ही, परेषण के पैकेजों को इस रीति से मोहरबन्द करेगा जिससे कि वह सुनिश्चित हो जाय कि मोहरबन्द किए गए माल में अन्तःक्षेप न किया जा सके। अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता की इच्छा हो, तो अभिकरण द्वारा पारेषण को मोहरबन्द नहीं भी किया जा सकता है। किन्तु, ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकेगा।

(5) जब अभिकरण ने अपना यह समाधान कर लिया है कि पाइप फिटिंगों का परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के सात दिन के भीतर, निर्यातकर्ता को यह घोषणा करने वाला प्रमाण पत्र देगा कि परेषण निर्यात योग्य है:

परन्तु, जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुआ हो, वहां वह उक्त सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा।

(6) जब कभी भी अभिकरण को आवश्यकता होगी, तब निर्यातकर्ता निर्यात वाले परेषण में से पाइप फिटिंगों के नमूने मुफ्त देगा। किन्तु, नमूने आवश्यक निरीक्षण तथा परख के पश्चात् अभिकरण द्वारा लौटा दिए जाएंगे।

5. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के प्रयोजन के लिए पाइप फिटिंगों का निरीक्षण

(क) विनिर्माता के परिसर पर, या

(ख) उस परिसर पर, जहां पर निर्यातकर्ता द्वारा पाइप फिटिंगें प्रतिस्थापित की जाती हैं, परन्तु यह तब जब कि वहां पर इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों, किया जाएगा।

6. निरीक्षण फीस: इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में, न्यूनतम पचास रुपए के अधीन रहते हुए, पोत तक निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपये के लिए पचास पैसे की दर से फीस दी जाएगी।

7. अपील: (1) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, ऐसे विशेषज्ञों के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये जायें, तीन से अन्यून किन्तु सात से अनधिक के पैनल को अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य अशासकीय होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी।

(4) अपील का निपटारा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर कर दिया जायेगा।

उपाबन्ध—III

पाइप फिटिंगों के लिये विनिर्देश

1. सामग्री—पाइप फिटिंगें इस्पात या आघातवर्धनीय ढलवा लोहे से विनिर्मित की जायेंगी।

2. कठोरता—सामग्री की कठोरता इस्पात फिटिंगों के लिये 120 बी०एच०एन० से तथा आघातवर्धनीय ढलवां लोहे की फिटिंगों के लिये 217 बी०एच०एन० से अधिक नहीं होगी।

3. विमायें, भार तथा सह्यतायें—विमायें, भार तथा सह्यतायें भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुसार होंगी। निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये विशेषज्ञों के पैनल द्वारा जब तक अनुमोदित न हो, कोई भी विचलन अनुज्ञात नहीं होगा।

4. दोषों से मुक्ति—फिटिंगें एकसार होंगी तथा ऐसे दोषों जैसे दरारों, क्षतिकर अनुप्रस्थ झोलों, पपड़ों, छेदों, पटलनों, आदि से मुक्त होंगी। पेंच चूड़ियां भली प्रकार कटी हुई होंगी। तथा खुरदरेपन से मुक्त होंगी। सिरे फिटिंगों के अक्ष के अनुरूप होंगे।

5. द्रवस्थैतिक परख—परख की जाने पर प्रत्येक फिटिंग क्षरण का कोई भी लक्षण प्रकट किये बिना 50 एम०जी० एफ० / से०मी०^2 का दाब सहन करेगी।

6. गैलवनीकरण—(i) फिटिंगें काले धब्बों, फफोलों तथा स्पेल्टर की गोलिकाओं आदि जैसे दोषों से मुक्त होगी।

(ii) फिटिंगों पर जस्ता कोटिंग का न्यूनतम भार 400 ग्रा०/मि० मी०^2 होगा।

(iii) कापर सल्फेट के घोल (मानक पद्धति के अनुसार) में लगातार चार बार डुबाई जाने पर, जिनमें से प्रत्येक डुबकी एक मिनट की होगी, फिटिंग चौथी डुबकी के पूरे होने के पश्चात् आधार धातु पर ताम्र का कोई लाल निक्षेप प्रदर्शित नहीं करेगी।

7. जिन फिटिंगों में गैलवनीकरण की आवश्यकता नहीं है उनका भंडारकरण तथा अभिवहन के दौरान मौसमी की अवस्थाओं के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षात्मक के लिये उपयुक्त संरक्षात्मक (भीतर और बाहर दोनों ओर) उपचार किया जायेगा।

8. पैकिंग—जबकि फिटिंगें सामान्य व्यापार पद्धति के अनुसार पैक की जायेंगी, फिटिंग के चूड़ी कटे सिरों को बाह्य नुकसान से यथोचित संरक्षा की जायेगी।

[सं० 6(20)/74-ई०आई० और ई०पी०]

के० वी० बालसुब्रह्मणियन, उप-निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 11th October, 1975

S.O. 4499.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), pipe fitting should be subject to quality control and inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby published the said proposals for the infromation of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publication of this Order in the Gazette of India to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th floor), Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that pipe fittings shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of inspection in accordance with the draft Export of Pipe Fittings (Quality Control and Inspection) Rules, 1975, set out in Annexure-II to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such pipe fittings;

(3) To recognise the specifications as declared by the exporter to be the agreed specification of the export contract for pipe fittings subject to minimum of specifications set out in Annexure-III to this Order as the standard specifications for pipe fittings;

(4) To prohibit the export in the course of international trade of any such pipe fittings unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the Export Inspection Agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the pipe fittings satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are export worthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of Samples of pipe fittings to prospective buyers, the f.o.b. value of which does not exceed rupees one hundred and twenty five.

4. In this order 'pipe fittings' shall mean, fitting manufactured from steel or malleable cast iron. Some of the common fittings are given in Annexure-I to this order.

ANNEXURE-I

1. Sockets
2. Pieces
3. Long Screws (connectors)
4. Bends
5. Springs
6. Return Bends
7. Nipples
8. Elbows
9. Tees
10. Crosses
11. 'Y' pieces
12. Caps
13. Plugs
14. Back Nuts
15. Unions
16. Bushes
17. Reducers.

ANNEXURE-II

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Export of Pipe Fittings (Quality Control and Inspection) Rules, 1975.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

(b) 'Agency' means any of the Export Inspection Agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under section 7 of the Act.

(c) 'pipe fittings' means fittings manufactured from steel or malleable cast iron. Some of the common fittings are given in Annexure-I.

3. Basis of inspection:—Inspection of pipe fittings for export shall be carried out when the consignment is ready with a view to seeing that the same conforms to the specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) Any exporter intending to export pipe fittings shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export contract giving details of all the technical characteristics to any one of the Export Inspection Agencies to enable it to carry out inspection in accordance with rule 3. He shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Export Inspection Council nearest to the office of the agency. The addresses of the Council are as under:—

Head Office:

Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1-B, Ezra Street, 7th floor, Calcutta-700001.

Regional Offices :

1. Export Inspection Council, Aman Chambers, 4th floor, 113, Maharshi Karve Road, Bombay-400004.

2. Export Inspection Council, Manohar Buildings, Mahatma Gandhi Road, Ernakulam, Cochin-11.

3. Export Inspection Council, 13/37, Western Extension Area, Arya Samaj Road, New Delhi-5.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall reach the office of the Agency and the Council not less than two weeks before the scheduled date of shipment.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (2), the Agency shall carry out the inspection of pipe fittings in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard.

4. After completion of inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(5) When the agency is satisfied that the consignment of pipe fittings complies with the requirements of rule 3 it shall within seven days of completion of inspection ,issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is export-worthy.

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefore.

(6) As and when required by the Agency, the exporter shall supply free of charge samples of pipe fittings from the export consignment. The samples shall, however, be returned by the Agency after necessary inspection and testing.

5. Place of inspection :—Inspection of pipe fittings for the purpose of these rules shall be carried out—

(a) at the premises of the manufacturer, or

(b) at the premises at which the pipe fittings are offered by the exporter, provided adequate facilities for the propose exist therein.

6. Inspection fee:—A fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of f.o.b. value subject to a minimum of rupees fifty shall be paid as inspection fee under these rules.

7. Appeal:—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4 may within ten days of receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of not less than three but not more than seven such exports as may be appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the panel of exports shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXUE-III

Specification for Pipe Fittings

1. Material.—The pipe fittings shall be manufactured from steel or malleable cast iron.

2. Hardness.—The material hardness shall not exceed 120 BHN for steel fittings and 217 BHN for malleable cast iron fittings.

3. Dimensions, weights and tolerances.—The dimensions, weights, and tolerances shall be as per Indian or any other national standard. No deviations shall be permitted unless approved by a panel of exports constituted by the Export Inspection Council for the purpose.

4. Freedom from defects.—The fittings shall be smooth and free from defects such as cracks, injurious flaws, fines, dents, lamination, etc. The screw threads shall be well cut and free from burrs. The ends shall be square to the exis of the fittings.

5. Hydrostatic test.—Each fittings, when tested, shall withstand a pressure of 50 Mgf/cm^2 without showing any sign of leakage.

6. Galvanising :

(i) The fittings shall be free from defects such as, black sports, blisters and globules of spelters.

(ii) The fittings shall have a minimum weight of 400 gms/mm^2 of zinc coating.

(iii) The fittings when subjected to four successive dips in copper sulphate solution (as per standard practice) each lasting one minute, shall not show any red deposit of copper upon the base metal after the completion of fourth dip.

7. The fittings which do not require galvanising, shall be given suitable protective (both inside and outside) treatment to safeguard against adverse effects of weather conditions during storage and transit.

8. Packing.—Whereas fittings shall be packed as per normal trade practice, threaded ends of the fittings shall be suitable protected against external damage.

[No. 6(20)/74-EI & EP]

K. V. BALASUBRAMANIAN, Dy. Director

87 GI/75—4

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का०आ० 4500.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 1199, तारीख 23 मार्च, 1973 को अधिक्रांत करते हुए, उत्तरवर्ती राज्य सरकारों और राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से व्यास सन्निर्माण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार

सदस्य

2. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के मुख्य मंत्री;

3. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में से प्रत्येक का एक-एक मंत्री जो अपनी-अपनी सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

4. उप-मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार;

5. उप-सिंचाई मंत्री, भारत सरकार ;

6. सचिव, भारत सरकार, विद्युत् विभाग, ऊर्जा मंत्रालय;

7. अपर सचिव, भारत सरकार, सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय ;

8. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार/सदस्य (जल-विद्युत्), केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत सरकार;

9. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय;

10. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, विद्युत् विभाग, ऊर्जा मंत्रालय;

11. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के सिंचाई और विद्युत् के भारसाधक सचिव;

12. राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग का भारसाधक सचिव और व्यास परियोजना का भारसाधक सचिव;

13. पंजाब हरियाणा और राजस्थान सरकारों के वित्त भारसाधक सचिव;

14. वित्त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश,

15. महाप्रबन्धक, व्यास परियोजना;

16. अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड;

17. अध्यक्ष, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य राज्य विद्युत् बोर्ड;

18. मुख्य इंजीनियर (विद्युत्), व्यास परियोजना;

19. वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, व्यास परियोजना;

20. मुख्य इंजीनियर (सिंचाई) पंजाब, मुख्य इंजीनियर (नहर), हरियाणा और मुख्य इंजीनियर, राजस्थान नहर परियोजना;

और बोर्ड को निम्नलिखित कृत्य समनुदेशित करती है, अर्थात् :—

(क) व्यास परियोजना का जिसे इसमें इसके पश्चात् परियोजना कहा गया है दक्षता, किफायत और शीघ्रतापूर्वक सन्निर्माण जिसमें पहले से प्रारम्भ किये गये किसी कार्य को, किन्तु भाखड़ा दक्षिण तट बिजली घर (भाखड़ा राइट बैंक पावर हाउस) स्थित 120 मेगावाट क्षमता की पंचम उत्पादन-यूनिट को छोड़कर, पूरा करना सम्मिलित है; और

(ख) परियोजना के संबंध में सभी अन्य कृत्य, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(1) परियोजना प्राक्कलनों की छानबीन और उनमें कोई उपान्तरण करना और केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के लिये प्राक्कलनों की सिफारिश करना—

(2) ऐसी तकनीकी और वित्तीय दोनों, शक्तियों को, जो बोर्ड आवश्यक समझे, महाप्रबन्धक और परियोजना के निष्पादन के लिये नियोजित अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना;

(3) परियोजना के विभिन्न भागों के सन्निर्माण का विनियमन और सिंचाई तथा विद्युत् प्रसुविधाओं के शीघ्र उपयोग के बहुचरणीय कार्यक्रम को तैयार करना;

(4) संबंधित सरकारों को जलग्रहण क्षेत्र की बाबत उपयुक्त भूमि संरक्षण उपायों की सिफारिश करना;

(5) संबंधित सरकारों को मत्स्यपालन के विकास के लिये उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

(6) परियोजना के सन्निर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उपयुक्त उपायों को अपनाना;

(ग) कोई अन्य कृत्य, जो खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं कृत्यों का अनुपूरक, आनुसंगिक या पारिणामिक हो—

2. बोर्ड का एक सचिवालय, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी और ऐसे अन्य कर्मचारिवृन्द होगा, जो आवश्यक हो।

3. बोर्ड (महा प्रबन्धक, वित्तीय सलाहकार, मुख्य इंजीनियर (विद्युत्) और बोर्ड के सचिव को छोड़कर, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी) ऐसे कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक हों।

[फा०सं० 17/128/67-बी०एण्ड बी०-जिल्द-3]

सी०एस०हुकमानी, उप-सचिव।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 4500.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), and in supersession of the notification of the Government of India in late Ministry of Irrigation and Power, No. S.O. 1199, dated the 23rd March, 1973, the Central Government, in consultation with the Governments of the successor States and the State of Rajasthan, hereby constitutes the Beas Construction Board (hereinafter referred to as the Board) consisting of the following persons, namely :—

CHAIRMAN

(1) The Minister of Energy, Government of India,

Members

(2) The Chief Ministers of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan

(3) One Minister each from the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan to be nominated by the respective Governments;

(4) The Deputy Minister, Ministry of Energy, Government of India;

(5) The Deputy Minister for Irrigation, Government of India.

(6) The Secretary to the Government of India, Department of Power, Ministry of Energy;

(7) The Additional Secretary to the Government of India, Department of Irrigation, Ministry of Agriculture and Irrigation ;

(8) Chairman, Central Water Commission, Government of India/Member (Hydro Electric), Central Electricity Authority, Government of India;

(9) The Joint Secretary to the Government of India, Department of Expenditure, Ministry of Finance;

(10) The Joint Secretary to the Government of India, Department of Power, Ministry of Energy;

(11) The Secretaries in charge of Irrigation and Power of the Government of Punjab, Haryana and Rajasthan;

(12) The Secretary in charge of Colonisation Department and the Secretary in charge of the Beas Project in the Government of Rajasthan ;

(13) The Secretary in charge of Finance of the Governments of Punjab, Haryana and Rajasthan;

(14) The Financial Commissioner-cum-Secretary, Revenue Department, Himachal Praedsh;

(15) The General Manager, Beas Project;

(16) The Chairman, Bhakra Management Board;

(17) The Chairman, State Electricity Boards of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Rajasthan;

(18) The Chief Engineer (Electrical), Beas Project;

(19) The Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Beas Project.

(20) The Chief Engineer (Irrigation) of Punjab, the Chief Engineer (Canals), Haryana and the Chief Engineer Rajasthan Canal Project.

and assigns to the Board the following functions, namely:—

(a) The construction, in an efficient, economical and expeditious manner, of the Beas Project (hereinafter referred to as the Project) including the completion of any work already commenced but excluding the fifth generating Unit of 120 MW capacity at Bhakra Right Bank Power House, and

(b) all other functions in relation to the Project, including—

(i) scrutiny of the Project estimates and making of any modification thereto and recommending the estimates for the administrative approval of the Central Government;

(ii) delegation of such powers, both technical and financial, as the Board may deem necessary, to the General Manager and other officers employed on the execution of the Project;

(iii) regulation of the construction of different parts of the Project and preparation of a phased programme of early utilisation of irrigation and power benefits;

(iv) recommending to the concerned Governments suitable soil conservation measures in respect of the catchment areas;

(v) recommending to the concerned Governments suitable measures for the development of pis-culture;

(vi) undertaking of suitable measures for the rehabilitation of persons displaced consequent on the construction of the Project;

(c) any other function which is supplemental, incidental, or consequential to all or any of the functions specified in clauses (a) and (b).

2. The Board shall have a Secretariat, Financial Adviser and Chief Accounts Officer and such other staff as may be necessary.

3. The Board may appoint such staff (other than General Manager, Financial Adviser, Chief Engineer (Electrical) and Secretary to the Board who shall be appointed by the Central Government), as may be necessary for the efficient discharge of its functions.

[F. No. 17/128/67-B&B-Vol. III]
C. S. HUKMANI, Dy. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का०आ० 4501.—पैट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (i) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला के लिये भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(ii) के पृष्ठ संख्या 2538 से 2542 तक दिनांक 12-7-75 को प्रकाशित का०आ० संख्या 2210 के द्वारा भारत सरकार, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12017/7/74-एल०एण्ड एल०, II दिनांक 2-7-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़ें।

अनुसूची

गांव : बारेजा तालुका : दसक्रोई जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

के स्थान पर		पढ़ें	
क्रमांक	तक	क्रमांक	तक
	एच०ए०वर्ग मीटर		एच०ए० वर्ग मीटर
1782/1	0-05-35	1782/1	0-06-35
2073/1	0-06-00	2073/2	0-06-00
गांव : जेतलपुर	तालुका : दसक्रोई	जिला : अहमदाबाद	गुजरात राज्य
1602/2	0-10-92	1602/2	0-05-92
1627 पी०	0-14-96	1627 पी०	0-04-96
1631/3	0-13-52	1631/3	0-13-92
गांव : नाज	तालुका : दसक्रोई	जिला : अहमदाबाद	गुजरात : राज्य
202	0-07-80	202	0-07-04
200	0-00-04	200	0-00-12
गांव : श्रोदी	तालुका : दसक्रोई	जिला : अहमदाबाद	गुजरात : राज्य
155	0-08-19	155	0-08-96
गांव : बकरोल-बद्राबाद बाकोला-बद्राबाद	तालुका : दसक्रोई	जिला : अहमदाबाद बकरोल . बद्राबाद	गुजरात : राज्य
गांव : बिसालपुर बैसालपुर	तालुका : दसक्रोई	जिला : अहमदाबाद बिसलपुर	गुजरात : राज्य

[सं० 12017/7/74-एल०एंड एल०/2]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 26th September, 1975

ERRATUM

S.O. 4501.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/7/74-L&L/II dated 2nd July, 1975 published vide S. O. No. 2210 dated 12 July 1975 from page No. 2538 to 2542 of the Gazette of India Part II Section 3(ii) for Taluka Daskrol District Ahmedabad Gujarat State, under sub Section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Village : Bareja Taluka : Daskroi District : Ahmedabad Gujarat State

For		Read	
S.No.	Extent	S.No.	Extent
	H.A.Sq.M		H.A.Sq.M
1782/1	0.05-35	1782/1	0-06-35
2073/1	0-06-00	2073/2	0-06-00
Village : Jetalpur	Taluka : Daskroi	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
1602/2	0-10-92	1602/2	0-05-92
1627 P	0-14-96	1627 P	0-04-96
1631/3	0-13-52	1631/3	0-13-92
Village : Naj	Taluka : Daskroi	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
202	0-07-80	202	0-07-04
200	0-00-04	200	0-00-12
Village : Ode	Taluka : Daskroi	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
155	0-08-19	155	0-08-96
Village : Bakrol-Badrabad	Taluka : Daskroi	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
Bakol-Badrabad		Bakrol-Badrabad	
Village : Visalpur	Taluka : Daskroi	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
Visalpur		Visalpur	

[No. 12017/7/74-L&L/II]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का०आ० 4502.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 3425 तारीख 17-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बंधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

डी०एस० नं० के० 66 से जी०जी०एस० 11 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टर	ए आर ई	गैण्टी ए आर ई
1	2	3	4	5
सैज	403/5	0	05	85
	कार्ट-ट्रेक	0	01	12
	514	0	04	35
	516	0	01	00
	513/1	0	01	00
	515	0	11	40
	517/3	0	04	50
	517/5	0	11	40
	517/8	0	03	45
	कार्ट-ट्रेक	0	00	60
	536	0	04	80
	535	0	06	67
	कार्ट-ट्रेक	0	00	75
	664	0	08	18
	665/1/ए	0	04	50
	665/1/बी	0	04	05
	665/2/बी	0	04	80
	659/1/ए	0	02	88
	659/1बी	0	03	53
	659/3	0	03	60
	659/2	0	00	50
	658	0	06	75
	712	0	15	90

[सं० 12016/9/74-एल०एंड एल०/2]

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4502.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S. O. No. 3425 dated 17-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under such section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule apended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from D.S. No. K-16 to GGS-II

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hactare	Are	Centiare
Saij . . .	403/5	0	05	85
	Cart-Track	0	01	12
	514	0	04	35
	516	0	01	00
	513/1	0	01	00
	515	0	11	40
	517/3	0	04	50
	517/5	0	11	40
	517/8	0	03	45
	Cart-Track	0	00	60
	536	0	04	80
	535	0	06	67
	Cart-Track	0	00	75
	664	0	08	18
	665/1/A	0	04	50
	665/1/B	0	04	05
	665/2/B	2	04	80
	659/1/A	0	02	85
	659/1/B	0	03	53
	659/3	0	03	60
	659/2	0	00	50
	658	0	06	75
	712	0	15	90

[No. 12016/9/74-L & L/II]

का० आ० 1503.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1967 (1967 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 3426 तारीख 17-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के० 164 से सी० टी०एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात तालुका : कालोल जिला : मेहसाना

गांव	ब्लाक सं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
धामासना	826	0	09	23
	827	0	11	25
	829	0	15	38

[सं० 12016/9/74-एल०एण्ड एल०/III]

टी०पी० सुब्रह्मनियम, अवर सचिव

S.O. 4503.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3426 dated 17-12-1974 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Aquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline From K-164 Yo CTF

State : Gujarat Taluka : Kalol District : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dhamasana	826	0	09	23
	827	0	11	25
	829	0	15	38

[No. 12016/9/74-L & L/III]

T. P. SUBRAMANIAN, Under Secy.

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई, 18 सितम्बर, 1975

का० आ० 4504.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग
1	2
प्रशासन अधिकारी, भारी जल परियोजना (तलचर) परमाणु ऊर्जा विभाग, डाकघर—तलचर उर्वरक नगरी जिला—धेनकनाल उड़ीसा राज्य	भारी जल परियोजना (तलचर), तलचर, जिला धेनकेनाल उड़ीसा राज्य में के प्रबन्ध के या उसके अधीन स्थान

[फा० सं० 13/2/73—(एच)]

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 18th September, 1975

S. O. 4504.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises
(1)	(2)
Administrative Officer, Heavy Water Project (Talchar), Department of Atomic Energy Post Office—Talchar Fertilizer Township, District—Dhenkanal Orissa State.	Premises belonging to or under the Management of Heavy Water Project (Talchar) at Talchar, District—Dhenkanal Orissa State.

[File No. 13/2/73-(H)]

का० आ० 4505.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, न्यूक्लीय ईंधन सम्मिश्रण, परमाणु ऊर्जा विभाग, मौला अली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में परमाणु ऊर्जा विभाग को या उसके प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन स्थान ।

[फा० सं० 13/2/73-(एच)]

त्रिलोक सिंह, अवर सचिव

S. O. 4505.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) , the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being a gazetted officer of Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, and further directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officers, by or under the said Act, within th local limits of his jurisdiction in respect of public premises specified in coloumn (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Senior Administrative Officer, Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Moula Ali, Hyderabad, Andhra Pradesh	Premises belonging to or under the administrative control of the Department of Atomic Energy in Hyderabad District of Andhra Pradesh

[File No. 13/2/73-(H)]

TARLOK SINGH, Under Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

का० आ० 4596—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 2, 7 और 8 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के आदेश सं० का० आ०/ आई डी आर ए/ 6/5 दिनांक 12 फरवरी, 1975 द्वारा पुनर्गठित और स्थापित ऊर्जा के जनित्रण, परिषण तथा वितरण हेतु (घरेलू काम में आने वाले मीटरों और नल पैमानों को छोड़कर) बिजली की मोटरों तथा मशीनों

और उपकरणों के निर्माण अथवा उत्पादनरत भारी विद्युत उद्योगों की विकास परिषद् का तत्काल से सदस्य-सचिव नहीं रहेगा :—

1. डा० वकील अहमद, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्ति को उपर्युक्त परिषद् का सदस्य-सचिव भी नियुक्त करती है :—

1. श्री आर० के० गुप्ता, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :

क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

29. श्री आर० के० गुप्ता, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली

[सं० ई० ई० आई०-19 (40)/74)]
एच० एल० अहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 1975

S.O. 4506.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 7 & of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby orders that the following person shall cease with immediate effect to be the Member-Secretary of the Development Council for Heavy Electrical Industries engaged in the manufacture or production of electric motors and of machinery and equipment for the generation, transmission and distribution of energy (excluding house service meters and panel instruments) which was reconstituted and established by Order No. S.O. IDRA/6/5 dated the 12th February, 1975 of the Government of India, Ministry of Industry & Civil Supplies, Department of Heavy Industry.

1. Dr. Vakil Ahmed, Development Officer, DGTD, New Delhi. Member-Secretary.

The Central Government also appoints the following person to be the Member-Secretary of the aforesaid Development Council :

1.Shri R. K. Gupta, Development Officer, DGTD, New Delhi. Member-Secretary.

The Central Government also directs that the following amendment shall be made in the said Order :—

For Serial No. 29 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted :—

"29. Shri R. K. Gupta, Development Officer, DGTD, New Delhi. Member—Secretary.

[No. EEI-19(40)/74]

H. L. AHUJA, Under Secy.

(Department of Civil Supplies & Co-operation)

New Delhi, the 29th September, 1975

CORRIGENDA

S.O. 4507.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Co-operation) No. S.O. 779 dated the 27th February, 1975 and published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii), dated the 8th March, 1975.—

1. at page 982—

(a) in item No. III, in the proposed clause (4) of Article 6(b).—in line 7, *for* "descretion" *read* "discretion";

(b) in item No. V, in the proposed clause (iii) of Article 7.—in line 1, for "provision" read "provisions".

2. at page 983—

(a) in item No. XVIII, in the proposed amendment to clause (i) of Article 47.—
in lines 2 and 3, for "Special Associate Member Class B or an Associate Member", read "Special Associate Member Class A or Special Associate Member Class B or an Associate Member";

(b) in item No. XX, in the words proposed to be added to clause (1) of Article 59.—
in line 2, for "penal" read "panel".

[F. No. 13(2)-IT/74]

U. S. RANA, Dy. Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 1975

का० आ० 4508—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक समिति गठित करती है जिसके निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

1. श्री पी० सी० मैथ्यू, आई० सी० एस० (सेवा-निवृत्त) अध्यक्ष
2. डा० के० सी० पील, सलाहकार, योजना आयोग, नई-दिल्ली सदस्य
3. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि सदस्य
4. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, एवं सांख्यिकी विभाग के वित्तीय सलाहकार सदस्य
5. निदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन एवं पदेन अपर सचिव, सांख्यिकी विभाग सदस्य
6. उप-सचिव, सांख्यिकी विभाग सदस्य सचिव

और उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं, अर्थात् :—

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान जिन कार्यों को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता द्वारा पूरा किये जाने का करार हुआ है, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था करेगी उन कार्यक्रमों को सूचित करने वाले विवरण एवं उनसे सम्बद्ध सामान्य वित्तीय अनुमान तैयार करना तथा केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(ख) कार्यक्रम की रूपरेखा संबंधी बन्दोबस्त ।

2. उक्त समिति अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 1976 तक प्रस्तुत करेगी ।

3. उक्त समिति के सचिवालीय कार्य सांख्यिकी विभाग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

[सं० एम०-12011/5/75-रा० प्र० सर्व-1]

हरीश चन्द्रा, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 4508.—In exercise of the conferred by sub-section (i) of Section 8 of the Indian Statistical Institute Act, 1959, the Central Government hereby constitutes a Committee consisting of :—

1. Shri P. C. Mathew, ICS (Retd.) Chairman
2. Dr. K. C. Seal, Adviser, Planning Commission, New Delhi. Member
3. A representative of the Indian Statistical Institute, Calcutta. Member
4. Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Expenditure and Financial Adviser to the Department of Statistics. Member
5. Director, Central Statistical Organisation and ex-officio Additional Secretary, Deptt. of Statistics. Member
6. Deputy Secretary, Department of Statisics. Member-Secretary.

and assigns the following duties to the Committee, namely :—

(a) preparation and submission to the Central Government of statements showing programmes of work agreed to be undertaken by the Indian Statistical Institute, Calcutta, during the year 1976-77 for which the Central Govt. may provide funds, as well as general financial estimates of such work; and

(b) the settlement on board lines of the programme of work.

2. The Committee shall submit its report by the 31st January, 1976.

3. The Department of Statistics will perform the secretariat functions of the Committee, the headquarters which will be at New Delhi.

[No. M. 12011/5/75-NSS. I]

HARISH CHANDRA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का० आ० 4509.—यतः भारतीय परिचर्या परिषद् ने भारतीय परिचर्या परिषद् अधिनियम 1947 (1947 का 48) की धारा 10 की उप-धारा (2) के अनुसरण में 6 सितम्बर, 1973 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए एक संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि उस में निर्दिष्ट अर्हता उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक मान्य अर्हता होगी :—

और यतः उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उक्त संकल्प को भारतीय परिचर्या परिषद् की 5 दिसम्बर, 1973 की अधिसूचना के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के परन्तुकों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है ताकि इसे उक्त घोषणा के अनुरूप लाया जा सके अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की अनुसूची के प्रथम भाग में शीर्षक "क-सामान्य परिचर्या के अधीन प्रविष्टि 47 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि रख ली जाए, अर्थात् :—

"18. श्रीमती नत्थी बाई दामोदर,
थेकरसे विश्वविद्यालय,
बम्बई । (जब 15 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद प्रदान की गई हो) ।"

[सं० वी० 14025/2/75-एम० पी० टी०]

ए० पी० अत्री, उप-सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 4509.—Whereas the Indian Nursing Council has, by a resolution passed at a meeting held on the 6th September, 1973, in pursuance of sub-section (2) of Section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), declared that the qualification specified therein shall be a recognised qualification for the purposes of the said Act;

And whereas the said resolution has been published in the Official Gazette with the notification of the Indian Nursing Council No. 11-1/73-INC, dated the 5th December, 1973, as required by sub-section (1) of section 15 of the said Act;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Schedule to the said Act so as to bring it in to accord with the said declaration, namely :—

In the Schedule to the said Act, in Part I, under the heading "A—General Nursing" after entry 47, the following entry shall be inserted, namely :—

"48. Shrimati Nathibai Damodar, Thackersey University, Bombay (when granted on or after the 15th April, 1969."

[No. V. 14025/2/75-MPT]

A. P. ATRI, Dy. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4510.—भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०ओ० 3151, दिनांक 15 जुलाई, 1972 के साथ प्रकाशित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (कलकत्ता) नियमावली 1972 के नियम 1 के उप-नियम (3) के खण्ड (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमावली को 1 दिसम्बर, 1975, से कलकत्ता के निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू करती है :—

1. विधान सरानी औषधालय (संख्या 8, 168 विधान सरानी)—इस औषधालय के अधीन डाक जोन 5, 6-7 और 9 के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र होंगे और जोन 9 का लगभग सारा भाग होगा (किन्तु

इसमें महात्मा गांधी रोड के दक्षिण में पड़ने वाला भाग शामिल नहीं है ।)

भौगोलिक दृष्टि से यह औषधालय पश्चिम में हुगली नदी, हावड़ा पुल से स्यालदे स्टेशन तक दक्षिण में महात्मा गांधी रोड, पूर्व में महात्मा गांधी रोड जंकशन से मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट तक आचार्य प्रफुल राय रोड गैस स्ट्रीट जंकशन से सर्कुलर केनाल जंकशन तक पूर्व की ओर वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है । पूर्व की ओर सर्कुलर केनाल से डाक जोन संख्या 6 की उत्तरी सीमा और उत्तर में डाक जोन 6 और 5 का उत्तरी सीमा का क्षेत्र इस औषधालय के अन्तर्गत आता है ।

2. मिण्ट कालोनी औषधालय संख्या 9 (मिण्ट गार्ड हाऊस)—इस औषधालय के अधीन डाक जोन 53, 38 तथा डाक जोन 18 व 60 का एक हिस्सा (साउथ सबअरबन म्युनिसिपलिटी के दक्षिण में वार्ड 3 तथा 32 और दक्षिण नगरपालिका के वार्ड 1,2,4, 11,12,13 और 16 के क्षेत्र आते हैं ।

इस औषधालय की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है :—

यह रेलवे लाइन से बज-बज रोड जंकशन तक पश्चिम में तारातला रोड (ब्रेस ब्रिज के पास) उत्तरी भाग पूर्व में टोली नाला से इसके जंकशन तक पुराने टोलीगंज रोड और विरेन राय रोड (पूर्व) दक्षिण में विरेन राय रोड (पूर्व) से इसके जंकशन डाइमण्ड हारबर रोड तक जो फकीर पारा लेन तक फैला है, इसके साथ साथ बेचु राम चटर्जी रोड; पश्चिम में, बेचराम चटर्जी रोड (फकीर पारालेन से) काजीपारा रोड, बनमाली नस्कर रोड (पार्नसारी पल्ली) (साऊथ सब-अरबन म्युनिसिपलिटी का वार्ड 3) से तारातला रोड के साथ इसके जंकशन तक और उत्तर पश्चिम में, ब्रेस ब्रिज के निकट रेलवे लाइन तक बज-बज रोड के क्षेत्र से घिरा हुआ इलाका ।

विनय बादल दिनेश बाग अथवा बी० बी० डी० बाग औषधालय (क्रम सं० 10)—भौगोलिक दृष्टि से यह औषधालय उत्तर में, हावड़ा पुल से आचार्य प्रफुल्ल राय रोड जंकशन तक महात्मा गांधी रोड (स्यालदे रेलवे स्टेशन के पास); पूर्व में, आचार्य प्रफुल्ल राय रोड (स्यालदे स्टेशन से) और आचार्य जगदीश बोस रोड; दक्षिण में, देवेन्द्र रोड और रेस कोर्स के साथ-साथ आचार्य जगदीश बोस रोड के जंकशन; पश्चिम में, रेस कोर्स जिसमें फोर्ट विलियम का इलाका व महात्मा गांधी रोड के साथ-साथ स्ट्रेण्ड रोड और इसका जंकशन वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है ।

यह औषधालय कलकत्ता पोस्टल जोन 1, 12, 13, 69, 16 और 21 तथा डाक जोन 9 और 14 के कुछ भाग में रहने वाले लोगों की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करेगा ।

[सं० एस० 11012/2/75-सी० जी० एच० एस०]

पी० वी० हरिहरणंकरन्, उप-सचिव

ORDER

New Delhi, the 3rd October, 1975

S.O. 4510.—In pursuance of clause (i) of sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Calcutta) Rules, 1972, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning No. S.O. 3151, dated the 15th July, 1972, the Central Government hereby extends the said rules with effect from the 1st December, 1975 to the following areas in Calcutta, namely :—

1. Bidhan Sarani Dispensary (No. VIII at 168, Bidhan Sarani).

This dispensary will cover postal delivery zones 5, 6, 7 and 9 almost the entire portion of postal zone No. 9 (except that falling south of Mahatma Gandhi Road.)

Geographically this Dispensary is bounded by Hoogly River in the West, Mahatma Gandhi Road in the South from Hawrah Bridge to Sialdh Station, Acharya Prafullah Roy Road in the East from the junction with Mahatma Gandhi Road to the junction of Madan Mohan Burman Street, proceeding East from the junction of Gas Street upto the junction of circular canal. In the East circular canal upto the Northern boundary of P.Z. No. 6. In the North, Northern Boundary of Postal Delivery Zone No. 6 and 5.

2. Min. colony Dispensary (No. IX (at 9 Mint Guard House).

This Dispensary will cover Postal Delivery Zones 53, 38 part of postal delivery zones 18, 60 (covering ward No. 3 South of Sub-urban Municipality and No. 34 (covering ward Nos. 1, 2, 4, 11, 12, 13 and 16 of South Subarban Municipality).

Geographically this Dispensary is bounded by Port Commissioner's Canal extended to Railway Line upto the junction of Budge Budge Road with Taratala Road (Near Brace Bridge) in the North; In the East by Tolly's Nala upto its junction with Old Tollyganj Road and Biren Roy Road (East); In the South by Biren Roy Road (East) upto its junction with Deamon Harbour Road extended to Fakirpara Lane upto its junction with Becharam Chatterjee Road; In the West by Becharam Chatterjee Road (from Fakir Para Lane), Kazi Para Road, Banamali Naskar Road including Parnsari Palli (ward No 3 of South Sub-urban Municipality) upto its junction with Tara-Tala Road and Budge Budge Road upto Railway Line near Brace Bridge in the North West.

Binoy Badal Dinesh Bag or B.B.D. Bag Dispensary (No. X) at 13 Old Court House Street, Calcutta).

Geographically this Dispensary is bounded in the North by Mahatma Gandhi Road from Howrah Bridge to the junction of Acharya Prafullah Roy Road (near Sealdah Railway Station; In the East by Acharya Prafullah Roy Road (from Sealdah Station) and Acharya Jagdish Bose Road; In the South by Acharya Jagdish Bose Road upto its junction with Debendra Road and Race Course ; In the West by Race Course including Fortwilliam extended to Strand Road upto its junction witht Mahatma Gandhi Road.

This Dispensary will cover Calcutta Postal Delivery Zones 1, 12, 13, 69, 16 and 21 and part of Postal Delivery Zones 9 and 14.

[No. S. 11012/2/75-CGHS]

P V. HARIHARASANKARAN, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 4511.—केन्द्रीय सरकार, विमान वहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में प्रमाणित करती है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित उच्च संविदाकारी पक्षकार, उसके स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों की बाबत, वारसा में 12 अक्तूबर, 1929 को जिसे हेग प्रोटोकल द्वारा 28 सितम्बर, 1955 को संशोधित किया गया है, हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय विमान वहन से संबंधित कतिपय नियमों के एकीकरण में अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार होंगे ।

सारणी

अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार	वे राज्य क्षेत्र जिनकी बाबत वे पक्षकार हैं
1	2
अफगानिस्तान	अफगानिस्तान
अल्जीरिया	अल्जीरिया

1	2
अर्जेन्टाईना	अर्जेन्टाईना
आस्ट्रेलिया	पपुआ, नारफाक द्वीप, न्यूगिनी
आस्ट्रिया	आस्ट्रिया
बैल्जियम	बैल्जियम
ब्राजील	ब्राजील
बुलगारिया	बुल्गारिया
बायलो रूसीसोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक	बायलो रूसी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक
कैमरून	कैमरून
कनेडा	कनाडा
कोलम्बिया	कोलम्बिया
कांगो लोकगणराज्य	कांगों लोक गणराज्य
क्यूबा	क्यूबा
साईप्रस	साईप्रस
जेकोस्लोवाकिया	जेकोस्लोवाकिया
दाहोमी	दाहोमी
डेनमार्क	डेनमार्क
डोमिनिकन गणराज्य	डोमिनिकन गणराज्य
एकोडर	एकोडर
मिस्र, अरब गणराज्य	मिस्र, अरब गणराज्य
एल साल्वेडर	एल साल्वेडर
फीजी	फीजी
फ्रांस	फ्रांस
गेबन	गेबन
जर्मनी प्रजातन्त्र गणराज्य	जर्मनी प्रजातन्त्र गणराज्य
जर्मनी संघ गणराज्य	जर्मनी संघ गणराज्य
यूनान	यूनान
ग्वाटेमाला	ग्वाटेमाला
हंगरी	हंगरी
आईसलैण्ड	आईसलैण्ड
भारत	भारत
ईराक	ईराक
आयरलैण्ड	आयरलैण्ड
इजराईल	इजराईल
इटली	इटली
आईवरी कोस्ट	आईवरी कोस्ट
जापान	जापान
जार्डन	जार्डन
कोरिया, गणराज्य	कोरिया, गणराज्य
लाओस	लाओस
लीबियन अरब गणराज्य	लीबियन अरब गणराज्य
लीकलेन्सताइन	लीकलेन्सताइन
लक्समबर्ग	लक्समबर्ग
मैडागास्कर	मैडागास्कर
मलावी	मलावी
माली	माली
मिसको	मक्सिको
पाल	नेपाल
नीदलैण्ड्स अधि-राज्य	नीदरलैण्ड्स अधि-राज्य
न्यूजीलैण्ड	न्यूजीलैण्ड
नाईजर	नाईजर
नाईजीरिया	नाईजीरिया
नार्वे	नार्वे
पाकिस्तान	पाकिस्तान
परागुवे	परागुवे
फिलिपाइन्स	फिलिपाइन्स
पोलैण्ड	पोलैण्ड
पुर्तगाल	पुर्तगाल
रुमानिया	रूमानिया
सऊदी अरब	सऊदी अरब
सेनेगल	सेनेगल
सिंगापुर	सिंगापुर
दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य	दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य
स्पेन	स्पेन
स्वाजीलैण्ड	स्वाजीलैण्ड
स्वीडन	स्वीडन
स्विटजरलैण्ड	स्विटजरलैण्ड
सीरिया	सीरिया
ट्यूनीशिया	ट्यूनीशिया
यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ	यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ
युनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड	युनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड
युनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड	बहमास, बरमुदा, ब्रिटिश अंटार्कटिक राज्यक्षेत्र, ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह, केमेन, तुर्कस और कैकस द्वीपसमूह ऐक्रोटिरी और धेकेलिया (साईप्रस के राज्य क्षेत्र) फाकलैण्ड द्वीपसमूह और अधीन क्षेत्र जिब्राल्टर, गिलबर्ट और एलिस द्वीपसमूह हांग-कांग, माण्टसेर्राट, सेंट हेलेना और एसेंशन, सेक्लीज, ब्रिटीश सोलोमन द्वीपसमूह संरक्षित देश
वेनेजुएला	वेनेजुएला
युगोस्लाविया	युगोस्लाविया
जाम्बिया	जाम्बिया

[फा० सं० 5-ए/73-69]

एस० एकाम्बरम, उप-सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, 29 September, 1975

S.O. 4511.—In pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972) the Central Government hereby certifies that the High Contracting Parties mentioned in column 1 of the Table below shall be the High Contracting Parties to the Convention for the unification of certain rules relating to the International Carriage by Air signed at Warsaw on the 12th day of October, 1929, as amended by the Hague Protocol on the 28th day of September, 1955, in respect of territories specified in the corresponding entry in column 2 thereof,

TABLE

High Contracting Parties to the Convention	Territories in respect of which they are parties
1	2
Afghanistan	Afghanistan
Algeria	Algeria
Argentina	Argentina
Australia	Papua, Norfolk Island, New Guinea
Austria	Austria
Belgium	Belgium
Brazil	Brazil
Bulgaria	Bulgaria
Byelorussian Soviet Socialist Republic	Byelorussian Soviet Socialist Republic
Cameroon	Cameroon
Canada	Canada
Colombia	Colombia
Congo, People's Republic of the Cuba	Congo, People's Republic of the Cuba
Cyprus	Cyprus
Czechoslovakia	Czechoslovakia
Dahomey	Dahomey
Denmark	Denmark
Dominican Republic	Dominican Republic
Ecuador	Ecuador
Egypt, Arab Republic of El Salvador	Egypt, Arab Republic of El Salvador
Fiji	Fiji
France	France
Gabon	Gabon
Germany Democratic Republic	Germany Democratic Republic
Germany, Federal Republic of Germany	Germany, Federal Republic of Germany
Greece	Greece
Guatemala	Guatemala
Hungary	Hungary
Iceland	Iceland
India	India
Iraq	Iraq
Ireland	Ireland
Israel	Israel
Italy	Italy
Ivory Coast	Ivory Coast
Japan	Japan
Jordan	Jordan
Korea, Republic of	Korea, Republic of
Laos	Laos
Libyan Arab Republic	Libyan Arab Republic
Liechtenstein	Liechtenstein
Luxembourg	Luxembourg
Madagascar	Madagascar
Malawi	Malawi
Mali	Mali
Mexico	Mexico
Nepal	Nepal
Netherlands, Kingdom of the	Netherlands, Kingdom of the
New Zealand	New Zealand
Niger	Niger
Nigeria	Nigeria
Norway	Norway
Pakistan	Pakistan
Paraguay	Paraguay
Philippines	Philippines
Poland	Poland
Portugal	Portugal
Romania	Romania
Saudi Arabia	Saudi Arabia
Senegal	Senegal
Singapore	Singapore
South African Republic of	South Africa, Republic of
Spain	Spain
Swaziland	Swaziland
Sweden	Sweden
Switzerland	Switzerland
Syria	Syria
Tunisia	Tunisia
Ukrainian Soviet Socialist Republic	Ukrainian Soviet Socialist Republic
Union of Soviet Socialist Republics	Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United Kongdom of Great Britain and Northern Ireland	Bahamas, Bermuda, British Antarctic Territory British Honduras, British Virgin Islands Caymen, Turk and Caicos Islands Akrotri and Dhekelia (Territories of Cyprus) Falkland Islands and Dependencies Gibraltar, Gilbert and Ellice Islands Hong Kong Montserrat,, St. Helena and Ascension Sechelles, British Solomon Islands Protectorate
Venezuela	Venezuela
Yugoslavia	Yugoslavia
Zambia	Zambia

[F. No. 5-A/73-69]

S. EKAMBARAM, Dy. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का० आ० 4512.—केन्द्रीय सरकार, काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1893, तारीख 9 मई, 1969 को अधिक्रांत करते हुए, भारतीय खाद्य निगम, काण्डला को उक्त स्कीम का दैनंदिन प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक निकाय के रूप में नियुक्त करती है।

[फा० सं० बी०-17025/6/74-एल डी]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 4512.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1893, dated the 9th May, 1969, the Central Government hereby

appoints the Food Corporation of India, Kandla, as the Administrative Body for carrying on the day to day administration of the said Scheme.

[File No. V-17025/6/74/LD]

का० आ० 4573.—केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित स्कीम का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है।

2 कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनयमन) स्कीम, 1970 के खण्ड 2 के उपखण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"(5) पोतों के मास्टर, डेरिकों की सज्जा और फिटिंग करने के लिए और अनुसूची 3 में अधिकथित सभी कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए बन्दरगाह कर्मीदल के सिवाय पोत के आबद्ध कर्मीदल को नियोजित कर सकेंगे। उन पोत परिवहन कंपनियों को जिनके कर्मशाला स्थापन हों और जो प्रथम अगस्त, 1955 से पूर्व डेरिकों की सज्जा और फिटिंग करने के लिए अपने कर्मशाला कर्मचारिवृन्द को नियोजित करती रही हैं, ऐसा करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। अन्य सभी दशाओं में, समुचित प्रवर्ग के बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत कर्मकार, ऐसे कार्य के लिए और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों की अभ्यपेक्षा पर ऐसे काम के लिए नियुक्त किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनार्थ,—

(1) "आबद्ध कर्मीदल से" पोत परिवहन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विनिर्दिष्ट अभ्यपेक्षा पर पोत परिवहन कंपनियों को, प्रधान आफिसर वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा भर्ती किया गया और दिया जाने वाला कर्मीदल अभिप्रेत है। ऐसा कर्मीदल, पोतों के फलक पर तभी लगाया जाता है, जब वह किसी या किन्हीं विशिष्ट समुद्र यात्राओं के लिए पोत के "आबद्ध कर्मीदल के रूप में हस्ताक्षर कर दे और उसे समुद्र यात्राओं के दौरान और किन्हीं भारतीय या विदेशी पत्तनों पर ठहरने के दौरान कप्तानों के निदेशानुसार पोतों को चलाने या उनके अनुरक्षण के कार्य में लगाया गया हो;

(2) "बन्दरगाह कर्मीदल" से पोत परिवहन कंपनियों द्वारा पोत कर्मीदल की मांगों को पूरा करने के लिए केवल दैनिक आधार पर लगाया गया कर्मीदल अभिप्रेत है। ऐसे कर्मीदल, इंजन-कक्ष में मरम्मत करने वाले कर्मचारिवृन्द और अनुरक्षण-कर्मचारिवृन्द के सहायकों के रूप में लगाए जाते हैं और वे पोत के मास्टर के निदेशानुसार कार्य करते हैं।

[फाइल संख्या यू-20025/3/74-एल डी]

S.O. 4513.—The following draft of a Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

2. For sub-clause (5) of clause 20 of the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, the following shall be substituted, namely :—

"(5) The Masters of Ships may engage the articled crew of the Ship, excluding harbour crew, for rigging and fitting of derricks and for carrying out all the functions and duties as laid down in Schedule III. The Shipping Companies who have workshop establishments and who have been employing before the 1st August, 1955 their workshop staff for rigging and fitting of derricks may also be permitted to continue to do So. In all other cases, registered workers of the Board of appropriate category shall be employed for such work and on requisition made by registered employers.

Explanations : For the purposes of this sub-clause :—

(1) "articled crew" means the crew enrolled and supplied to the Shipping Companies by the Principal Officer, Mercantile Marine Department on specific requisition submitted by the Shipping Companies. Such crew are engaged on board the ships after they sign on as 'articled crew' of the ship for a particular voyage or voyages and are engaged to look after running or maintenance of the ships as per the directions of the Masters while during the voyage and during the stay at any Indian or foreign port;

(2) "harbour crew" means the crew engaged by the Shipping Companies to meet the demands of ships crews purely on day to day basis. Such crews are engaged as helpers to the repairing staff and maintenance staff in engine room and work as per directions given by the Master of the ship."

[File No. U-20025/3/74-LD]

का० आ० 4514.—कलकत्ता डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 437, तारीख 21 जनवरी, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 फरवरी, 1975 के पृष्ठ 610—11 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 26 फरवरी, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) तृतीय संशोधन स्कीम 1975 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2 कलकत्ता डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 में ,—

(क) खण्ड 20 के उपखण्ड (1) की मद (ख) में, "और साथ ही साथ उसके पास ऐसी फीस जमा करेगा जो उस निमित्त विहित की जाए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड 44 के उपखण्ड (5) में, "और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) खण्ड 45 में—उपखण्ड (1) की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"रजिस्ट्रीकृत नियोजक जो खण्ड 41 (1) (i) के अधीन कार्यपालक अधिकारी के आदेश से व्यथित, अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और तब वह उसका विनिश्चय करेगा ।" ;

(घ) उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) वह नियोजक जिसे खण्ड 13 (1) (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार किया गया है, अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार अपील पर ऐसा आदेश करेगी । जैसा वह उचित समझती है ।"

(ङ) खंण्ड 48 में, उपखण्ड (2) में—

(i) मद (i) की उपमद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी नियोजक की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उपमद (ख) के अधीन इस प्रकार हटाया नहीं जाएगा" ;

(ii) मद (ii) की उपमद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तुक कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उपमद (घ) के अधीन कोई ऐसी समाप्ति या उपमद (ङ) के अधीन पदच्युति नहीं की जाएगी ।"

[एस० 68013/2/71-पी एण्ड डी/एल डी]

वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

S.O. 4514.—Whereas certain draft scheme to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 610—11 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 15th February, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 437, dated the 21st January, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th February, 1975 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970, namely :—

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Third Amendment, Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970 :—

(a) in item (b) of sub-clause (1) of clause 20 the words, "and simultaneously deposit with him such fees as may be prescribed in this behalf," shall be omitted;

(b) in sub-clause (5) or clause 44, the words "and the order passed on such appeal shall be final and conclusive" shall be omitted ;

(c) in clause 45—for item (a) of sub-clause (1), the following shall be substituted, namely :—

"A registered employer who is aggrieved by an order of the Executive Officer under clause 41(1) (i) may prefer an appeal to the Chairman and thereupon he shall decide the same";

(d) for sub-clause (2) the following shall be substituted, namely :—

"(2) An employer who has been refused registration under clause 13(1) (a) may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit."

(e) in clause 48, in sub-clause (2) (i) after sub-item (b) of item (i), the following proviso shall be added, namely :—

'Provided that no such removal under sub-item (b) shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard" ;

(iii) after sub-item (e) of item (ii) the following proviso shall be added, namely :—

Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard."

[S-68013/2/71-P&D/LD]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

पुनर्वास विभाग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० आ० 4515.—निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा 3 द्वारा मुझे महाअभिरक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इस विभाग

की अधिसूचना संख्या 1 (16)/विशेष सैल/75-एस० एस० ii दिनांक 1 अगस्त, 1975 द्वारा नियुक्त हरियाणा राज्य के सहायक महाअभिरक्षक को महाअभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

(1) अधिनियम की धारा 24 तथा 27 के अन्तर्गत शक्तियां ।

(2) अधिनियम की धारा 10(2)(o) के अन्तर्गत किसी निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तांतरण को स्वीकृत करने की शक्तियां ।

(3) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 30-क के अन्तर्गत मामलों को हस्तांतरित करने की शक्ति ।

[संख्या 1(16)/विशेष सैल/75-एस० एस०II]

ध० कृष्ण अय्यर, महाअभिरक्षक

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 24th September, 1975

S.O. 4515.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by sub-section 3 of section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to the Assistant Custodian General for the State of Haryana, appointed vide this Department's notification No. 1(16)/Spl. Cell/75-SS. II dated the 1st August, 1975, the following powers of the Custodian General :—

(1) Powers under Section 24 and 27 of the Act.

(2) Powers of approval of transfer of any evacuee property under Section 10(2)(o) of the Act.

(3) Power of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1955.

[No. 1(16)/Spl. Cell/75-SS. II]

D. KRISHNA AYYAR, Custodian General

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 जून, 1975

का० आ० 4516.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ईस्ट मुरलीडिह कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 8, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता की ईस्ट लोहापट्टी कोलियरी, डाकघर रामनगरगढ़, जिला धनबाद जो अब मैसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के अधीन है, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स ईस्ट मुरलीडिह कोल कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 8, वाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता, की ईस्ट लोहा पट्टी कोलियरी, डाकघर रामनगरगढ़ जिला धनबाद जिसका प्रबन्ध 31 जनवरी, 1973 से केन्द्रीय सरकार ने ग्रहण कर लिया है और जो अब मेसर्स कोल माइन्स अथारिटी लिमिटेड, 15, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता के प्रबन्धतन्त्र के अधीन है, के प्रबन्धतन्त्र की, 30 अक्तूबर, 1972 से श्री सीताराम महतो, सर्फेस ट्रैमर को पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल० 20012/72/73-एल० आर-2 डी-3(ए)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 3rd June, 1975

S.O. 4516.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Lohapathi Colliery, Post Office Ramnagar Garh, District Dhanbad, of Messrs East Murlidih Coal Company (Private) Limited, 8, Waterloo Street, Calcutta, and now under the management of Messrs Coal Mines Authority Limited, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of East Lohapati Colliery, Post Office Ramnagar Garh, District Dhanbad, of Messrs East Murlidih Coal Company (Private) Limited, 8, Waterloo Street, Calcutta, taken over by the Central Government from 31st January, 1973 and now under the management of Messrs Coal Mines Authority Limited, 15, Park Street, Calcutta, in dismissing Shri Sitaram Mahato, Surface Trammer, with effect from 30th October, 1972, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-20012/72/73/LRII/D.III(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975

का० आ० 4517—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धर्माबाद उप क्षेत्र, डाक-घर खरखरी, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या जोगीडिह कोलियरी से सम्बद्ध भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धर्मबिाद उपक्षेत्र डाकघर खरखरी, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की, श्री रामलखन साव साओ, पम्प खलासी को जो बिल लिपिक क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है, पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ।

[संख्या एल० 20012/120/74-एल० आर०-2-डी-3ए]

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1975

S.O. 4517.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharat Coking Coal Limited, Dharmabad Sub Area, Post Office Kharkharee, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bharat Coking Coal Limited, Dharmabad Sub-Area, Post Office Kharkharee, District Dhanbad, in relation to Jogidih Colliery, in dismissing from service Shri Ram Lakhan Sao, Pump Khalasi, working as Bill clerk is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-20012/120/74-LR II/DIIIA]

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

का० आ० 4518.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की निचितपुर कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की, सर्वश्री पेयारी भुइया, छकन भुइया, कारु भुइया, अर्जुन भुइया, किशुन भुइया, शेया शरण और रोहन भुइया, ट्रैमरों को आकस्मिक पूल में रखने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं ?

[संख्या एल०-20012/48/75 डी० 3ए]

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1975

S.O. 4518.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Nichitpur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad, is justified in keeping Sarva Shri Peyari Bhuia, Chhakan Bhuia, Karu Bhuia, Arjun Bhuia, Kishun Bhuia, Sheya Sharan and Rohan Bhuia, Trammers, in casual pool? If not, to what relief are the said workmen entitled and from what date ?

[No. L-20012/120/74-LR II/DIIIA]

आदेश

का० आ० 4519.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अंगरपाथरा कोलियरी की नेशनल अंगरपाथरा सेक्शन डाकघर कसरासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उन कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की अंगारपाथरा कोलियरी के नेशनल अंगारपाथरा सेक्शन डाकघर कसरासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की श्री चन्द्रेश्वर सिंह, हाजिरी मजदूर एवं रात्रि रक्षक को, 13 दिसम्बर 1971 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-20012/50/75-डी०-3(ए)]

ORDER

S.O. 4519.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of National Angarpathra Section of Angarpathra Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of National Angarpathra Section of Angarpathra Colliery of Messrs Bharat Coking Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad, in stopping Shri Chandeshwar Singh, Hazree Mazdoor-cum-Night Guard, from work with effect from the 13th December, 1971; is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

[No. L-20012/50/75-D-III(A)]

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975

का० आ० 4520.—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित औद्योगिक विवादों में न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो उसे उक्त अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं, एक श्रम न्यायालय गठित करती है, जिसका मुख्यालय कानपुर में होगा और श्री भृगु नारायण उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत सदस्य को उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस-11025/3/75-डी० के० आई० ए०(i)]

New Delhi, the 26th September, 1975

S.O. 4520.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes a Labour Court with headquarters at Kanpur, for the adjudication of industrial disputes relating to any matter specified in the Second Schedule to the said Act and for performing such other functions as may be assigned to it under the said Act, and appoints Shri Bhrigu Narain, retired Member of the Higher Judicial Service, Uttar Pradesh, as its Presiding Officer.

[S-11025/3/75.DKI.A]

का० आ० 4521.—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 4650, तारीख 19 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(क) क्रम सं० 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"11. भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 441, तारीख 29 जनवरी, 1965 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, जबलपुर।"	मध्य प्रदेश राज्य

(ख) क्रम सं० 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"21. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०-11025/3/75/डी० के० आई० II (i) तारीख 26/9/75 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, कानपुर।"	उत्तर प्रदेश राज्य

[सं० एस-1125/3/75-डी० के० आई० ए० (ii)]

S.O. 4521.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33C of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 4650, dated the 19th December 1967, namely:—

In the Table annexed to the said notification—

(a) for serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"11. Labour Court, Jabalpur, constituted under section 7 of the said Act, by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 441, dated the 29th January, 1975."	The State of Madhya Pradesh.

(b) after Serial number 20 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"21. Labour Court, Kanpur constituted under section 7 of the said Act, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S—11025/3/75. DKI—AI dated the 26th September 1975."	The State of Uttar Pradesh

[No. S-11025/3/75.DKI.A.]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 4522.—केन्द्रीय करकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1187 तारीख 2 अप्रैल 1975 द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल, 1975 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अक्तूबर 1975 से छः मास की और कालावधियम के लिए लोकउपयोगी सेवा घोषित करती है।

[एस० 11025/7/75-डी० के० आई० ए]

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4522.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the provisions of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1187 dated the 2nd April, 1975 the services in the uranium industry, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 20th April, 1975.

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 20th October 1975.

[S-11025/7/75. DKIA]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का० आ० 4522—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2279 दिनांक 22 जून, 1968 द्वारा गठित श्रम न्यायालय संख्या 3, धनबाद के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एस० एन० जौहरी को 18-9-75 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस० 11025/21/75 डी० 1 ए० (i)]

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 4523.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Labour Court No. 3, Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2279, dated the 22nd June, 1968;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Johri as the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect from the 18th September, 1975.

[No. S-11025/21/75/DIA.(i)]

का० आ० 4524—भारत सरकार के तत्कालीन श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या 2280 दिनांक 22 जून 1968 द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण संख्या 3, धनबाद के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एस० एन० जौहरी को 18/9/75 से उक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एस० 11025/21/75/डी० आई० ए० (ii)]

S.O. 4524.—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal No. 3 Dhanbad, constituted by the notification of the Government of India in the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 2280, dated the 22nd June, 1968;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Johri as the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect from 18th September, 1975.

[No. S. 11025/21/75 DIA.(ii)]

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4525—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि ताम्बा उद्योग को जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (न) के उपखण्ड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० एस०- 11017/7/75-डी- 1 (ए)]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

New Delhi, the 1st October, 1975

S.O. 4525.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Copper Mining Industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S. 11017/7/75/DIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer, (Spl.).

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1975

का० आ० 4526—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं० 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के प्रशासन की, श्री पी० आर० नायक, वैज्ञानिक सहायक 'ख' की सेवाएं 9/11/1974 से समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो श्री पी० आर० नायक किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल० 42012/2/75-डी-2 बी]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1975

S.O. 4526.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Tarapur Atomic Power Station and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial

Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the administration of Tarapur Atomic Power Station in terminating the services of Shri P. R. Naik, Scientific Assistant 'B' with effect from 9-11-1974 is justified ? If not, to what relief is Shri P. R. Naik entitled ?

[No. L-42012/2/75-D. IIB]

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का०आ० 4527.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स, दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या इंडियन एयर लाइन्स, दिल्ली क्षेत्र, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र का, श्री पी०एस० जस्सल, टेलिप्रिण्टर आपरेटर के 29 सितम्बर, 1966 और 10 फरवरी, 1967 को हुए सेवा भंग को माफ न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-11012(6)/75-डी-2 (बी)]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 26th August, 1975

S.O. 4527.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of India Airlines Delhi Region, New Delhi, and their workmen in respect of the matters, specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Indian Airlines, Delhi Region, New Delhi, is justified in not condoning the breaks in service on 29-9-1966 and 10-2-1967 of Shri P. S. Jassal, Teleprinter Operator ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 11012(6)/75-D. 2(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Special).

आदेश

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1975

का०आ० 4528.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कल्याणराम अभ्रक खान, कालीचेडु नेल्लोर जिला प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कल्याणराम अभ्रक खान, कालीचेडु, नेल्लोर, जिला के प्रबन्धतंत्र की, श्री ग्राला वेंकटैया, उत्स्फोटक (ब्लास्टर) को 9 मई, 1975 से पदच्युत करने की कार्यवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-28012(2)/75-डी-4 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 20th August, 1975

S.O. 4528.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kalyanrama Mica Mine, Kalichedu, Nellore District and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10. of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Narasinga Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Kalyanrama Mica Mine, Kalichedu, Nillore District in dismissing Shri Grala Venkataiah, Blaster with effect from the 9th May, 1975 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-28012/2/75-D-IV-(B).]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का०आ० 4529.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनैशनल, हासपेट की भारत रायान। हुडवा लौह अयस्क खानों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ)

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० भागवत होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल, हौसपेट की भारत रायाना हरुवा लौह अयस्क खानों के प्रबन्धतंत्र की, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25ख के उपबन्धों का अनुपालन किये बिना, श्री मोहम्मद खासिम की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-26012/10/75-डी-4 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 26th August, 1975

S.O. 4529.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bharat Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet and their workman in respect of the matter specified in the Schedule thereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Bharata Rayana Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet in terminating the services of Shri Mohammad Khasim without complying with the provisions of section 25F of the Industrial Disputes Act, 1947 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-26012/10/75-D-IV-(B).]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975

का० आ० 4530.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री लक्ष्मीधर मलिक, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के समक्ष लम्बित है;

और उक्त श्री लक्ष्मीधर मलिक की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं हैं;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 33ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को, जो उक्त श्री लक्ष्मीधर मलिक के समक्ष लम्बित हैं, वापस लेती है और उक्त कार्यवाहियों के निपटारे के लिये श्री बी०एन० मिश्र, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर को इस निदेश के साथ स्थानान्तरित करती हैं कि उक्त अधिकरण और आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाए, और विधि के अनुसार उसका निपटारा करेगा।

अनुसूची

क्रमांक	विवाद के पक्षकार	औद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या और तारीख
1.	मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के पेलेटाइजिंग संयंत्र का प्रबन्धतंत्र और उनके कर्मकार—श्री बी० के० मिश्र।	संख्या एल-29012/22/74-एल० आर०-4-डी-4 (बी), तारीख 21-2-1975 (का०आ० 891)

[संख्या एल-29012/22/74-एल०आर-4/डी-4 (बी)]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1975

S.O. 4530.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri Luxmidhar Mullick, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneshwar ;

And, whereas the services of the said Shri Luxmidhar Mullick are no longer available ;

Now, therefore, in exericse of the powers conferred by section 7A, and sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the said Shri Luxmidhar Mullick and transfers the same to Shri B. N. Misra, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Bhubaneshwar for the disposal of the said procedings with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Parties to the dispute	Reference No. and date of Industrial dispute
1.	Management of Polletizing Plant of Messers Tata Iron and Steel Company Limited and their workman Shri B. K. Mishra.	No. L-29012/22/74-LR. IV-D-IV (B) dated 21.2.1975. (S.O. 891).

[No. L-29012/22/74-LR. IV/D-IV (B).]

BHUPENDARA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त 1975

का० आ० 4531.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ इण्डिया से सम्बद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ इण्डिया उ० प्र० क्षेत्र, लखनऊ के प्रबन्धतंत्र का श्री हरीश कुमार रावल की सेवाएँ 4 फरवरी, 1975 से समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/86/75/डी-11ए]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4531.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of India, U. P. Region, Lucknow is justified in terminating the services of Shri Harish Kumar Rawal, with effect from the 4th February 1975? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-12012/86/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 4532.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि उससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से सम्बन्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोंधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, प्रदेश- IV नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र की, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, गोदाम रक्षक का स्थानान्तरण उक्त बैंक की फगवाड़ा शाखा से चौक कटरा खजाना अमृतसर शाखा में करने की कार्रवाई तंग करने का कार्य है ? यदि हाँ, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/87/75/डी०-II/ए]

ORDER

S.O. 4532.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India, Region IV, New Delhi, in transferring Shri Surinder Pal Singh, Godown Keeper from Phagwara Branch to Chowk Katra Khazana Amritsar Branch of the said Bank is an act of victimisation? If so, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/87/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1975

का० आ० 4533.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ मदुरई लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पलनियप्पन होंगे जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ मदुरई लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र की, निम्नलिखित कर्मकारों को जो बैंक आफ मदुरई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं, नीचे तथा वर्णित रूप में स्थानान्तरित करने की कार्रवाई तंग करने का कार्य है ? यदि हां, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं :—

(क) श्री के० रामलिंगम, महासचिव, उक्त बैंक की वल्पाराई शाखा के मदुरई तलाकुलम से ;

(ख) श्री आर० राजगोपाल, उपाध्यक्ष, उक्त बैंक की सलेम शैवपेट शाखा के मदुरई पौनागरम से ;

(ग) श्री एस० रामनाथन, कोषपाल, उक्त बैंक की इरोड शाखा के केन्द्रीय कार्यालय मदुरई से ।

[सं० एल 12011/11/75-डी०II/ए]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1975

S.O. 4533.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Madurai Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Madurai Limited on transferring the following clerks, who are the office bearers of the Bank of Madurai Employees' Union, as detailed below, is an act of victimisation? If so, to what relief are these workmen entitled—

(a) Shri K. Ramalingam, General Secretary from Madurai—Tallakulam to Valparai Branch of the said Bank ;

(b) Shri R. Rajagopal, Vice President, from Madurai—Pownagaram to Salem—Shevapet Branch of the said Bank ;

(c) Shri S. Ramanathan, Treasurer, from Central Office, Madurai to Erode Branch of the said Bank.

[No. L-12011/11/75-D. IIA]

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4534.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the Andhra Bank Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th September 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, BOMBAY

Reference No. CGIT-6 of 1973

PARTIES :

Employers in relation to the Andhra Bank Ltd.,

AND

Their Workmen.

PRESENT:

Shri B. Ramlal Kishen L.L.M. Bar at law, Presiding officer.

APPEARANCES :

For the employers—Shri V. V. Pai, Advocate.

For the workmen—Shri T. R. Hegde, Advocate

State—Maharashtra.

Industry—Banking.

Bombay, the 23rd August, 1975

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, have by their order No. L.12912/23/73/LRIII dated 30th August, 1973, made in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the Andhra Bank Ltd., and their workmen in respect of the subject matter specified in the following schedule :

SCHEDULE

"Whether the demand of the Andhra Bank Employees Union, Bombay for absorption of Smt. Dhanibhai as full-time sweeper by the Andhra Bank Ltd., in their Branch at Nanavati Mahal, Bruce Street, Bombay is justified? If so, to what relief is she entitled and from what-date?"

2. After the receipt of the order of reference notices were issued to the parties for filing their respective statements. The Andhra Bank Employees' Union has by its statement of claim submitted that Smt. Dhanibai was initially engaged as Sweeper by the Bank in 1962 on a temporary basis and was paid monthly emoluments not exceeding Rs. 27 per month and this continued till the year 1969; that in the year 1969 the union raised a dispute as regards the terms of her employment before the labour machinery of the Government of India and during the proceedings a settlement was reached and with effect from 24-12-1969. Smt. Dhanibai was confirmed as a part-time sweeper in the bank and all provisions relating to such confirmed employees set out in the settlement arrived at between the bank managements and their workmen on the 19th October, 1966 were made applicable to Smt. Dhanibai. The Union has submitted that at the time of confirmation of Smt. Dhanibai no question of her age arose and the confirmed employment was without prejudice to her age at that time and it is now not open to the Bank to raise or rely on rules for recruitment even, if any, relating to age exists, before this Tribunal. It is stated that in October, 1971 the Bank shifted its offices to more spacious premises wherein Smt. Dhanibai continued to work for 2¼ hours on every working day and continued to receive her wages in terms of the aforesaid Bi-Partite Settlement dated 19-10-1966. It is the case of the union that the Bank entrusted the increased work of cleaning of the new premises in addition to the work done by Smt. Dhanibai to a contractor viz., M/s Clean Well India, 232, Dr. D. N. Road, Bombay-1. It is stated that the said contractor sends regularly one sweeper for 4 to 5 hours daily on all week days for the work of cleaning. Furthermore 2 to 3 additional workers are posted by the contractor once in a week on every saturday to clean lights, fans, gass panes ceilings etc., and he is paid Rs. 400 per month for all the additional work. It is the contention of the Union that the availing of services of a sweeper for 4 to 5 hours daily on all week days is adequate proof that there is vacancy for a full time sweeper since the total hours of work of cleaning would be 2.1/2 hours done by Smt. Dhanibai plus 5 hours done by the contractors sweepers making a total of 7½ hours. The union therefore submits that its demand for engaging Smt. Dhanibai as a full time sweeper is justified as the working hours of a full time sweeper as per the Bi-Partite Settlement dated 10-10-1966 provide for a total of 39½ hours per week as against the number of hours of work which is required at present for sweeping, but not including the special work on a saturday, amounts to 45 hours per week. It is contended that it was not open to the Bank to fill the vacancy by having the sweeping work done by another sweeper also performed on the basis of part-time. It is further submitted that the provisions of para 20:6 of the Bi-Partite Settlement dated 19th October 1966 envisages that part-time employees will be given preference for filling full time vacancies. The Bank however, has not, given effect to this provision in the case of Dhanibai and has thus violated para 20:6 of the Bi-Partite Settlement. Not only that the bank has entrusted the supplementary sweeping work to a sweeper who is attached to a contractor and is thus also guilty of violation of section 29 of the Industrial Disputes Act. Finally, it is prayed that Smt. Dhanibai be absorbed as a full time sweeper by extension of her present part-time employment and that she be paid the emoluments of a full time sweeper with effect from the month of October 1971 from which date the deprivation of her employment as full time commenced together with all other service conditions applicable to confirmed full time sub-staff as provided for in the Bi-Partite Settlement dt. 19-10-1966 and later revised. It is also prayed that penal action may be taken against the employer under section 29 of the Industrial Disputes Act.

3. The Bank has by its written statement admitted that there was a settlement with the union in 1969 under which it had agreed to treat Smt. Dhanibai as a confirmed part-time employee on higher emoluments but has submitted that the terms of settlement are not disclosed by the union. It is the further submission of the bank that though the age of Smt. Dhanibai was much above the age at which members

of the subordinate staff could be recruited she was confirmed as a special case as she was to be only a part-time employee of the bank. It is denied that the bank had waived any objection or restriction as to the age for recruitment except for employment on a part-time basis. It is submitted that the contention of the union that the bank is precluded from relying on rules and policies in relation to the employment of Smt. Dhanibai is misconceived and untenable. It is further submitted that the union first complained to the Regional Labour Commissioner (Central), Bombay that Smt. Dhanibai was denied all work but had to admit the incorrectness of their claim when confronted with the real facts. According to the Bank their new premises are not only more spacious but maintaining its cleanliness involves an entirely different type of work besides sweeping; that sweeping is only a minor part of the work and the other work includes keeping the fixtures and electric equipment and installations clean and also involves work of keeping fixtures above the floor and on the ceiling clean. The cleaner sent by the contractor attends to sweeping also among other things. As regards Smt. Dhanibai it is the bank's case that a part from the lack of technical skill she is physically incapable of doing most of the work done through the contractor and his men and that was why the bank had to entrust the same to a competent contractor. But in order that Smt. Bhanibai may not suffer any prejudice she was continued in service in the new premises. It is further alleged that she has not been carrying out her duties properly and by and large the Contractor's man has to do the work which ordinarily has to be done by her. The Bank has submitted that it is not true that the sum of Rs. 400 per month paid to the contractor is only for the additional work, but according to the bank it is for keeping all the premises and fixtures clean. According to the Bank the time taken for sweeping by the contractor's man may not exceed an hour and a half per day and thereafter for other cleaning and conservancy work he may take about an hour and a half per day. In this connection the bank relies on the contract dated 2-9-1971 entered into between it and M/s Kleenwel (India), and renewed from time to time. The Bank has submitted that it is a wrong basis to add up the hours of work put in by various persons. It is comtended that sweeping, the work of keeping the premises and fixtures clean have to be done during particular hours of tthe day and by its very nature the work of sweeping cannot be done for more than two or three hours a day and if one person is not able to do it would be necessary to entrust it to someone else. Thus it is contended that there is not and cannot be any vacancy for a full-time sweeper in the bank's present office and it is also stated that even by adding up the hours of work put in by both Smt. Dhanibai and the contrac or's man the total hours per day will not exceed 5-1/2 hours per day. It is the case of the bank that the work of sweeping alone is not of 39-1/2 hours per week as alleged by the union, that the hours cannot be running hours for one person and thus the demand for engaging Smt. Dhanibai on a full time basis is unjustified, misconceived and untenable. The bank has submitted that if the contractor's men had not attended to the additional work the workload of Smt. Dhanibai would have increased and the same would have been beyond her capacity and therefore apart from other reasons the Bank had to entrust the said additional work to the contactor. In view to para 20 : 6 of the First Bi-Partite Settlement dated 19-1-1966 which is to the following effect :

> "Subject to a Bank's recruitment rules, if any, part time employees will be given preference for filling of full time vacancies, other things being equal."

The bank has submitted that there is no full-time vacancy of a sweeper and other things are not equal. Apart from this it is contended that according to the recruitment rules of the bank recruitment of persons above 25 years of age for subordinate posts on a permanent basis is prohibited. It is stated that when Shri Dhanibai was first engaged she was only taken as a temporary hand as she was then above 25. But because of pressure from the union to treat her service as a permanent one on compassionate grounds an exception was made as a special case. It is also asserted again that the work being done by the contractor's men is additional work and there is no violation under section 29 of the Industrial Disputes Act. According to the bank the question of absorption of Smt. Dhanibai as a full-time sweeper cannot and does not arise and the question of extension of part-time work is not possible. It is also submitted that absorption cannot be claimed with retrospective effect and any claim for work obviously not done is unjustified. It is finally stated that neither the union nor Smt. Dhanibai made any demand for over one year after shifting to the present premises and thereafter also came forth with an entirely false claim and in any event the union is estopped from raising the dispute.

4. The Bank later filed a supplemental written statement in which it has stated that it is an admitted fact that a conciliation settlement was reached by and between the Bank and the local employees union of the bank with regard to the workman Mrs. Dhanibai on 24th December, 1969 and it is also an admitted fact that such a conciliation settlement is vaid subsisting and binding on the bank as well as on all the employees working in the various establishments of the employer bank. It is therefore, submitted that this issue could not have been referred for adjudication when the aforesaid conciliation settlement continues to remain in force and is subsisting and the present reference should not be entertained by the Tribunal. This statement is filed as stated by the bank without prejudice to the submissions and contentions in its written statement.

5. In reply to the above supplemental statement of the bank the Secretary of the Andhra Bank Employees Union has submitted that the evidence in the matter has been recorded and the present, statement has been made mala fide with intention to delay the proceedings and or otherwise embarrass the proceedings. It is stated that there is no settlement pending or otherwise as to whether a full time vacancy has arisen regarding the employment of a sweeper; that the first party has not stated in its application any facts which is common to the alleged settlement of 24th December, 1969 and the matter referred for adjudication under this reference. It is submitted that there is no reference to this Tribunal as to whether there is any dispute pending between the parties herto and it is therefore beyond the scope of the issues referred to this Tribunal to decides to whether there is any industrial dispute capable of being decided by this Tribunal. It is further submitted that the issues in settlement dated 24th December, 1969 and the present reference are entirely different having arisen under different circumstances and are therefore liable to be separately decided on their own merits.

6. Two prelimnary issues arise for consideration at this stage in view of the stand taken by the employer viz.,

(1) Whether the Andhra Bank Employees' union had made a valid demand on the management for absorption as full time sweeper by the Andhra Bank, and

(2) Whether the reference is incompetent as alleged by the management.

7. It is contended before me by the learned Counsel for the management that there is no demand made by the workmen on the company seeking absorption of Smt. Dhanibai as full time sweeper. It does not become in industrial dispute and this Tribunal has no jurisdiction to entertain the reference. It is contended that the reference is bad in law and it should be rejected. It is also contended by the learned Counsel for the employers that the industrial dispute was only raised for the first time before the Conciliation Officer and as no demand was made prior to the commencement of the conciliation proceedings no industrial dispute existed before the Government referred this dispute to this Tribunal.

8. On the other hand the learned Counsel for the workmen argues that in paragraph 11 of the written statement the bank has taken up the plea that either the union or Smt. Dhanibai also did not make any demand for over one year after shifting to the present office premises and thereafter also came forth with an entirely false claim which indicates that the union had made a demand on the bank for absorption of Smt. Dhanibai as full time sweeper. It is argued that Conciliation Officer in paragraph 4 of this report had mentioned that the union representative had stated to have written several letters to the bank management requesting to restore the duties of Smt. Dhanibai at the new premises and absorb her in full time permanent vacancy of sweeper; but the management did not settle the issue. This fact had not been contradicted by the management. It is further mentioned that by application dated 27th August, 1974 the union had asked for the production of the personal file of Smt. Dhanbai and the bank

had stated in reply on 29th October, 1974 that there is no personal file of Smt. Dhanibai maintained by them. It is contended that if the respondent had produced the personal file of Smt. Dhanibai then the letters alleged to have been written by the union to the bank would have come to light which establishes the assertion of the representative of the union before the Conciliation Officer about sending several letters to the bank requesting the management to absorb Smt. Dhanibai in a full time permanent vacancy.

9. The question that now poses for determination is whether Smt. Dhanibai raised a demand with the management and whether the reference is competent ? The Delhi High Court in 1973 II LLJ 307 held that the first question is a preliminary issue of jurisdiction. The object of the Industrial Disputes Act, 1947, is to provide for 'the investigation and settlement of industrial disputes'. An industrial dispute as defined in s. 2(k) of the Act exists or is apprehended before it could be considered by the Conciliation Officer under section 12 of the Act and then referred to the Labour Court by the appropriate Government under section 12(5) read with sec. 10(1) of the Act. The concept of 'industrial dispute' is that a demand is made by the workman and is rejected by the employer. It is this demand and rejection which constitutes a dispute between these two parties. Following the judgement of the Supreme Court in Sindhu Resettlement Corporation Ltd. v. Industrial Tribunal of Gujarat (1968 I LLJ 834) A.I.R. 1968 S.C. 529, the Division Bench of the Delhi High Court in Fedders Lloyd Cor., (p) Ltd., v. Lt. Governor, Delhi, A.I.R. 1970 Delhi 60 held that an industrial dispute could not be said to exist unless and until a demand was made by the workman on the employer and it was rejected by the employer. Their Lordships observed that if the workman does not make a demand on the employer but directly goes to the Conciliation Officer then even if the demand is made before the Conciliation Officer and is not acceded to by the employer in the Conciliation proceedings, it could not be said that an 'industrial dispute' within the meaning of section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 existed between the workman and the employer. Though the reference is made by the Government on a consideration of the report of the Conciliation Officer under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947, the power of the Government to make the reference is derived from section 10(1) of the said Act which reads as follows :—

> "Where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time, by order in writing—
>
> (a) refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof; or
>
> (b) refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for inquiry; or (c) refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute, if it relates to any matter specified in the Second Schedule to a Labour Court for adjudication."

The only basis of the jurisdiction of the Industrial Tribunal is the reference of the dispute made to it by the Government. If the Government does not make a reference, the Labour Court does not get the jurisdiction to adjudicate on an industrial dispute under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947. The subject matter of the dispute may relate to any of the matters specified in the Second Schedule to the Act. These are within the exclusive jurisdiction of the Industrial Tribunal. But the fact and legality of the reference fall outside the subject matter of the dispute and is, therefore, not a matter which falls within the exclusive jurisdiction of the Industrial Tribunal. The question whether a demand was raised by the workman with the employer and was rejected by the employer is a jurisdictional fact being part of the definition of 'industrial dispute' which must exist before the reference can be made by the Government. The challenge to the legality of the reference by the employer both before the Labour Court and in this Court is based on the ground that no industrial dispute existed within the meaning of s. 2(k) of the Act.

10. The Supreme Court in Jaipur Udyog Ltd. v. The Cement Works Karmachari Sangh, Sahu Nagar (1972 I LLJ 437) following the decision in the Sindhu Resettlement Corporation Ltd., v. The Industrial Tribunal of Gujarat and others 1968 1 LLJ 834 held that unless a dispute was raised by the workman with the employer it could not become an industrial dispute. These two decisions of the Supreme Court therefore finally establish beyond doubt that a mere demand on the Government without a demand on their employers cannot become an industrial dispute. The above decision also establishes beyond doubt that the legality of a reference can be impugned by disproving its factual basis. These two decisions of the Supreme Court were followed by the Delhi High Court in Delhi Transport Corporation v. Delhi Administration and others 1973 II LLJ 307. It is true that in the State of Madras v. C.P. Sarathy 1953 I LLJ 174 the Supreme Court had observed that the Government acting under section 10(1) is doing an administrative act and the fact that it has to form an opinion as to the factual existence of an industrial dispute cannot be questioned by the Court while it is open to the employers to show that what was referred by Government was not an industrial dispute within the meaning of the Act. But in Newspapers Ltd., v. State Industrial Tribunal U.P.A.I.R. 1957 S. C. 532 it was held the rights of an aggrieved party to show that what was referred was not an industrial dispute at all even though the factual existence of a dispute may not be subject to such a challenge. Did the Supreme Court intend to exclude judicial review of facts in testing the legality of a reference under section 10(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 ? With great respect, it appears that no such rigid conclusion was reached by the Court in the above-mentioned two decisions. In C.P. Sarthy's case (supra) the contention of Prabhat Talkies was that no dispute existed between them and their workmen and therefore they should not have been included along with the other cinema theatres in the reference made by the Government to the Industrial Tribunal. This contention was negatived by the Court on two grounds. Firstly, it was said that the Labour Commissioner's report showed that an industrial dispute existed between the management and the employees of the cinema theatres. Secondly, a reference could be made even when a dispute was apprehended (though it may not be existing) and therefore Government had jurisdiction to make the reference even in respect of the Prabhat Talkies. In the case before me the question of dispute being apprehended did not arise at all. Either the dispute existed or it did not. In C.P. Sarathy's case (supra) a dispute was apprehended and it was not, therefore necessary to decide if it existed. In Newspapers Ltd., v. State Industrial Tribunal (supra) the question was purely one of law, namely, whether the dispute between a single workman and the employer was an 'Industrial dispute'. It would appear therefore that neither of these two decisions finally establish that judicial review of the factual basis of the reference was precluded in all circumstances. The observations pointing in that direction may, therefore, be respectfully regarded as obiter. However, in view of the decision of the Supreme Court in Sindu Resettlement Corporation Ltd., v. Industrial Tribunal, 1968 I LLJ 834 it will be futile to discuss the matter any further. It is now finally established by the Supreme Court that a mere demand to the Government without a dispute being raised with the employer cannot become an industrial dispute.

11. In this case before me the management has submitted in its written statement that it is significant to note that either the union or Smt. Dhanibai also did not make any demand for over one year after shifting to the present office premises and thereafter also came forth with an entirely false claim. According to the evidence of MW-1 the bank shifted to the present premises in October, 1971 and the dispute was referred to this Tribunal on 30th August, 1973. From the affirmations made in the statement of claim and written statement it cannot be clearly spelt out that the workman or union had made a demand on the management for absorption of Shrimati Dhanibai as a full time sweeper. It was incumbent on the workman to have established that a demand was directly made on the management before the initiation of the conciliation proceedings for absorbing Smt. Dhanibai as a full time sweeper. No such proof is forthcoming. It is no doubt true that the Conciliation Officer has observed in his report that the representative of the union had stated to have written several letters to the bank management requesting to restore the duties of Smt. Dhanibai at the new premises and absorb her in a full time permanent vacancy of sweeper. Even before the Conciliation Officer no attempt was made to produce or cause production of the said letters. There was no occasion for the management to have contradicted this statement of the representative of the union before the Conciliation Officer. If the union had written several letters to the management as alleged they could have submitted an application before this Tribunal for a direction to the management to produce those letters. But no such attempt was made. The union had merely called for the personal file of Smt. Dhanibai and the management had stated that they were not maintaining any personal file for Smt. Dhanibai. Apart from this, it does not stand to reason that the

personal file would contain letters addressed by the union to the management. If several letters had been written by the union to the management the union would surely have kept copies of those letters which they could have produced before this Tribunal and asked for a direction to the management to produce the originals. It is significant to note that MW-2 has stated on oath that the union did not demand that the workman in this reference should be made full time workman. No Cross-examination at all was directed to this aspect of the matter. Thus there is absolutely no evidence that an oral or written demand was directly made on the employer either by the workman or union raising an industrial dispute to absorb Smt. Dhanibai as a full time permanent sweeper in the bank. The demand for the first time was made only before the Conciliation Officer which is not sufficient.

12. As no dispute was raised by the workman with the management prior to the dispute being referred by the Government for adjudication the Government was not competent to make this reference. The preliminary objections raised by the management are sustained. The reference made by the Government is therefore incompetent and has to be rejected.

13. As the parties have led evidence before me on the merits and have addressed arguments I propose to deal with the merits of the reference which pertains to the issue whether the demand of the Andhra Bank Employees' Union for the absorption of Smt. Dhanibai as full-time sweeper by the Andhra Bank Ltd., in their branch at Nanavati Mahal, Bruce Street, Bombay, is justified ? It is submitted by the management that the claim of the union on behalf of Smt. Dhanibai is against the rules of recruitment of the bank; that there is no vacancy of a full-time sweeper in the present branch office; that the nature of work done by contractor's men is of a different nature and character and that the work is beyond the capacity, physical as well as technical of Smt. Dhanibai.

14. It is not open to controversy that Smt. Dhanibai was employed as a part-time sweeper in the Andhra Bank Ltd., and under the terms of settlement Ex-W-1 her pay with effect from 1-10-1969 was fixed. Before I discuss the evidence on record relating to the controversy between the parties it would be appropriate to refer to the various awards on the subject. The Sastry Award paragraph 498 provided that for ordinary clerical work no bank should employ part-time workers except for the writing of pass books in banks in which this practice now prevails. The first bi-partite settlement paragraph 20:4 provided that notwithstanding anything contained in paragraph 498 of the Sastry Award for pass-book writing all banks will be free to employ part-time clerks as pass book writers. Apart from such persons already in employment in future only students and retired persons (but in any case no person already in employment elsewhere) will be engaged by banks for this purpose and the hours of work will not exceed 12 hours in a week. Paragraph 20:5 lays down that banks will be free to readjust the working hours of the existing part-time workmen provided that the proportion of a workman's existing wages to the wages of a full-time workman in the appropriate cadre at the same stage in the existing scale and his existing total wages are not adversely affected. Paragraph 20:6 provided that subject to a bank's recruitment rules, if any, part-time employees will be given preference for filling of full-time vacancies, other things being equal. Paragraph 9 of the second bi-partite settlement provides that in supersession of clauses 4.5 and 20.5 of the Bi-partite Settlement dated 19th October, 1966 part-time workmen shall be entitled to graduated incremental pay scales related to their working hours as follows:—

(a) Part-time workmen other than those belonging to the subordinate staff shall be paid one-third of the "scale wages" and shall also be entitled to one-third of the annual increment payable under this settlement to full time workmen provided that the total working hours of such part-time workmen shall not exceed 12 per week.

(b) Part-time workmen who are members of the subordinate staff shall be paid :

If their normal total working hours per week are :	
Up to 3 hours ..	at Bank's discretion.
More than 3 hours but less than 6 hours. ..	at Bank's discretion but with a minimum of Rs. 25/- per month.
6 hours to 13 hours ..	One third of the scale wages with proportionate annual increment.
More than 19 hours to 29 hours : ..	Three-fourth of the scale wages with proportionate annual increment.
Beyond 29 hours.	—Full scale wages.

Explanation :

15. For the purpose of sub-clauses (a) and (b) above the expression scale wages shall mean basic pay, city compensatory allowance (as per clause 11 below) if any, special house rent/other allowance, if any, and dearness allowance payable under this Settlement to full time workmen.

16. In the light of the above rules the claim of the union has to be judged.

17. It is the assertion of the management that the claim of the union is against the rules of recruitment of the bank. MW-2 has deposed that exhibit M-1 is the recruitment rules which are incorporated in the form of resolution passed, by the Directors of the Board on 12-10-1974, and the same rules for recruitment to the sub-staff are being followed since the year 1971. Ex-M-1 is the resolution of the bank which lays down the qualifications for appointment of sub-staff that they should not have passed 8th standard, they should be below 25 years with a relaxation to the extent of the temporary services, if any, the candidate has put in the bank and preference will be given to retired defence personnel and in their cases exemption in age limit may be given to the extent of service put in by them in armed forces and appointment of sub-staff should be made from the local candidates only. Ex-M-1 came into force on 22-10-1974 after the reference. It was conceded by the bank that there were no rules laid dawn by the bank relating to preference to be given to part-time employees to fill up full time vacancies. Paragraph 20.6 of the first Bi-partite Settlement is to the effect that subject to a bank's recruitment rules, if any, part-time employees will be given preference for filling of full time vacancies, other things being equal. It is therefore abundantly clear that no rules were framed by the bank for filling up full time vacancies by part-time employees. The contention of the management therefore that the claim of the union on behalf of Smt. Dhanibai is against the rules of recruitment of the bank stands rebutted as there are no rules of the bank on the subject.

18. The second contention of the respondent is that there is no vacancy of full time sweeper in the present branch office and as such the claim of the union is speculative and this was also the argument of the learned Counsel for the bank. It was submitted by him that there is no vacancy of a full time sweeper in the bank in which Smt. Dhanibai could be absorbed. But the absence of a full time vacancy cannot detract from the claim of the union if there is sufficient work for a full time employee and the bank had employed others to perform the duties which could be performed by a part-time employee. It will have to be seen now whether there is sufficient work to justify the appointment of a full time sweeper. WW-4 is the contractor who has taken up the work of cleaning and sweeping the premises. He states in his evidence that he is the Proprietor of Kleenwel established in 1964. There are nearly 500 workers working in the company and all of them are engaged on cleaning and sweeping work. He has two electricians who are holding second class wiremen certificate. There are no other technicians in the company. He has got about 49 establishments and there are different categories of worker employed by him. There are about 250 on monthly paid basis. About 150 to 173 are working continuously for

more than one year. He produced a list of firms to whom the company rendered service. He states that there are two persons working at the Andhra Bank in Nanavati Mahal premises. They work from 7 a.m. to 10.30 a.m. Out of the two one breaks at 10.30 and the other continues the shift. One person attends the toilets and other attends the cleaning. After completing the toilet work that worker helps the other one. Internal bank work will be finished by 9 a.m. Thereafter the external job will be finished by about 10.30. Whatever is listed before office hours in ex. W-3 is finished before 10.30 a.m. It is done between 7 a.m. and 10.30 a.m. Out of the two one is toiletman who works full time. This man cleans the toilets and maintains the toilet. There are two toilets one for gents and the other for ladies. The toilet boy is relieved at 5.30 p.m. The work done by the workers is supervised by the mukkadam nad area supervisor. Ex-W-5 is the letter dated 2-9-1971 written by the witness to the Andhra Bank containing the enclosure. For cleaning the carpets it is stated that they have got vacuum machine operating on electrical and glass cleaning brush and other materials, brooms, dusters, brushes and cleaning materials are supplied to the workers who work.

19. MW-1 who is the Manager of the Andhra Bank deposes that the premises are about 4500 Sq. ft. both on the ground floor and basement inclusive. The flooring of the old premises was covered by linoleum and part of the flooring in the present premises is covered by woollen carpets and rest of the flovring is not covered by anything except mosaic tiles. In the present premises there are glass panels throughout and in the ceiling glass covering. The height of the ceiling is about 8-1/2 ft. from the floor. In the gents toilet there are two W. Cs. and two urinals and the ladies toilet has one W.C. The office hours are from 10.30 a.m. to 5.30 p.m. with a lunch interval of half hour. Dhanibai used to sweep the floor in the old premises and also the toilets. She used to come in the morning at 7.30 and worked for 2 to 2 1/2 hours. Thereafter she did not do any other work in the course of the day. In the present premises she used to clean the tiffin table between 12.30 p.m. and 2.30 p.m. when the staff have lunch in the tiffin room. They have engaged contractors to do the work of sweeping and cleaning the office premises. Glass cleaning and carpet cleaning requires special kind of work which the employee Dhanibai is not capable of doing. The work has to be done out of office hours both in the morning and in the evening, and they cannot ask Dhanibai beyond 7 p.m. as she is a female employee and for these reasons they have entrusted the work to the contractors. He says that the cleaning of the establishment is a daily routine and to his knowledge there was no complaint against Smt. Dhanibai about her work. He says that it is not correct to say that she was dusting the table and fans and she was cleaning the floor and toilets. He says that no special equipments are used for cleaning the premises except the vacuum cleaner. He says that she is not capable of removing the funnels of the ceiling, cleaning them and replacing them.

20. Smt. Dhanibai has stated that she was working as a sweeper in the bank since 13-14 years and she was getting Rs. 7 only when she joined the bank. She produced Ex. W-1 (copy of the settlement) and after the settlement her name was entered in the muster roll. She used to start work at 8 a.m. till 10.30 cleaning the furniture etc. and in the afternoon she used to clean the dining table, and this used to take her half an hour. This work she used to do at 18 Home Street from 8 a.m. to 10.30 a.m. She used to first sweep the ground floor and first floors thereafter she used to dust the furniture and then clean the bathroom and its walls with vim powder. With wet cloth she used to clean the floor and after the settlement she used to attend on Sundays also. On Sundays she used to clean the premises for five hours and wash the floors with water and vim. She used to put thumb impression on the muster roll. and the watchman generally used to mark the time of her arrival and departure in the muster. They have shifted from the old premises to the new premises at Bruce Street since about four years. The new premises are bigger than the old one. The work which the used to do prior to shifting to new premises was not given to her in the new premises and since no work was assigned to her she used to come to the new premises sit there and go back. She used to come at 12 noon and leave at 3.30 p.m. Some contractor was doing the cleaning and sweeping work in the premises. She says she can do the cleaning work etc., in the new premises as she used to do previously in the old premises. There was no complaint about her work during the period of 10 years of work with the bank and she is prepared to do the entire work of sweeping and clearing of the premises. Her age is 45 years. In cross-examination she has stated that she cleaned the canteen and cleaned the tables etc., after the employees of the Bank had taken lunch. She then cleaned the floor of canteen and the ladies bathroom. The manager of the bank had instructed her to clean the tiffin room. She was working in the tiffin room from 12.30 to 3.00 p.m. and thereafter she used to go to the ladies bathroom from 3 to 3.30 p.m. for cleaning it. There were fans fixed to the walls and there were tube lights and she used to clean these with cloth with the help of a table. There were carpets in the old premises. She used to clean the talpatris once a week and she was supplied by the bank, vim powder, acid bottles, phenyle, dusters, soaps and brooms of two types.

21. WW-2 has deposed that he is working as a peon-cum-watchman in the Andhra Bank since 1963. She knows that Smt. Dhanibai was a Sweeper and in the 1963 the bank's office was in Hamam street and at that time Dhanibai used to come at 8 a.m. and was doing the sweeping work upto 10 a.m. and he used to mark her attendance and note the time in the register. She used to sweep the premises and then dust the furniture glass panes and clean the bathroom. Phenyle, acid, vim powder etc., used to be supplied by him and she used to wash the floor with phenyle. She used to come on Sundays and Bank Holidays also for the same work at 8 a.m. and was working there till 11.30 or 12 noon. In cross-examination she has deposed that Dhanibai was coming at 12.30 noon and cleaning the ladies toilet, and then she washes the glasses in the staff tiffin room. She used to bring articles of food required by the staff members while taking lunch in the tiffin room and her work was over by 3.30 p.m. On saturdays she did the same work between 11.30 a.m. and 2.30 p.m. and she did not come on Sundays and holidays. The contractors men came from 8 a.m. to 10 a.m. only and they did not come in the afternoon. Some time they came in the evening after 6 a.m. but they did not do any work. Sometimes they used to come on Sundays and holidays but they worked only on Sundays and not on holidays. He says one man sweeps the basement and ground floor and the other man only cleans the two bathrooms. One man only dusts the furniture and fans but they do not clean the cupboards, typewriters and racks. The new premises is entirely enclosed by glass panels. The contractors men also clean the basement and the two bathrooms are cleaned by the contractors men as and when called. They collected the waste papers from the waster paper baskets after office hours. They do not clean the carpets after office hours. They clean the side glass walls but they do not clean the glass ceiling. They cleaned the pedestal fans once a week.

22. WW-3 is the President of the Bombay Unit of the Andhra Bank Employees Union and the Committee Member of the All India Andhra Bank Employees Union. He speaks about two part-time employees being absorbed permanently in the bank. He says that one Shri Vengal Rao working as sub staff at Hyderabad main Branch was confirmed in 1971 at the age of 36-37 and the other person is Shri Prakash Rao working as sub-staff at Vijayawada confirmed in 1971.

23. The above evidence clearly established that the new premises occupied by the bank is larger than the one previously occupied by them. There is more furniture, the floor is covered with woollen carpets and there are more bathrooms. The volume of work had increased and a part-time employee could not cope up with the work which led the management to employ a contractor to do the work. The mere fact that the management was constrained to appoint contractors for cleaning the new premises clearly manifests that there is increased in the volume of work and there is scope for the appointment of a full time sweeper. Although in the written statement of the bank a plea was taken that Smt. Dhanibai had not been carrying out her duties properly MW-1 the manager of the bank in his evidence before this Tribunal when cross-examined on behalf of the workmen has stated that to his knowledge there was no complaint against Smt. Dhanibai about her work. According to the workman her age is only 45 which has not been contradicted by the bank. It cannot be said therefore that she is not in a position to perform the duties of full time sweeper although it may be difficult for her to handle the vacuum cleaner and other equipment. But it was not difficult for her to clean the furniture dust the fans and the glass panes on the windows and in the ceiling. No suggestion was made to her in the witness box that she was unable to carry out the above work.

24. Now the question that arises is whether the bank was justified in employing a contractor to do the work of cleaning and sweeping in the bank. The Contract Labour (Regulation and Abolition Act) 1970 clearly forbids such employment unless the employer of an establishment to which the Act applies registers himself for this purpose. Section 9 lays down that no principal employer of an establishment to which this Act applies shall :

(a) in the case of an establishment required to be registered under section 7 but which has not been registered within the time fixed for the purpose under that section,

(b) in the case of an establishment the registration in respect of which has been revoked under section 8,

employ contract labour in the establishment after the expiry of the period referred to in clause (a) or after the revocation of registration referred to in clause (b) as the case may be. Section 7 provide for the registration of an employer employing contract labour. According to section 2, the Contract Labour Abolition Act, 1970, applies to any establishment of a banking or insurance company. There is no evidence placed on record by the management that the bank has registered itself under the above Act permitting it to employ contract labour. Therefore the employment of contract labour by the bank was entirely illegal. I therefore hold on the evidence on record that there was enough work in the bank to justify the appointment of a full time sweeper and Smt. Dhanibai should have been absorbed as a full time sweeper.

25. But I have already held on the preliminary objections raised by the employers that as no dispute was raised by the workman with the management prior to the dispute being referred by the Government for adjudication the Government was not competent to make this reference and it is therefore not possible for me to give any relief to the workman in this award. The reference is rejected.

Award is made accordingly.

No order as to costs.

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

[No. L-12012/23/73-LR III]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 4535.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री बी० अकम्मा रेड्डी को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए-12016(1)/72-पी० एफ०1]

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4535.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri B. Ankama Reddy to be an Inspector for the whole of the state of Orissa for the purposes of the said Act and the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/1/72-P.F.I]

का० आ० 4536.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० डी० शन्मुघम को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापना के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य और पान्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पाण्डीचेरी और करायकल क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए-12016(6)/72-पी० एफ० 1]

प्रसन्न चन्द्रा, अवर सचिव

S.O. 4536.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri S. D. Shanmugham, to be an Inspector for the whole of the State of Tamil Nadu and union territory of Pondicherry and Karkail area of the Pondicherry for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/6/74-PF. I]

PARSAN CHANDRA, Under Secy.

New Delhi the 30th September, 1975

S.O. 4537.—In pursuance of the section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following awards of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba 3/4 Pits Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Limited, P. O. Jealgora, District Dhanbad, and their workmen which was received by the Central Government on the 23rd September, 1975.

(AWARD)

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 19 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1974.

(Ministry's Order No. L-2012/49/74-LRII, dated 6-9-1974).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba 3/4 Pits Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Company Limited, P. O. Jealgora, District Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the Employers.—Shri S. S. Mukherjee Advocate.

On behalf of the Workmen.—None.

State : Bihar Industry : Coal

Dhanbad, dated the 18th September, 1975

AWARD

In this reference which was sent by the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved, two issues were framed, viz.

"(1) Whether the management of Jamadoba 3/4 Plts Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company Limited, Post Office Jealgora, District Dhanbad, were justified in downgrading Shri Nazir Mohammad, Pump Khalasi, from Category-III to Category-II on and from the 15th August, 1967 to the 31st December, 1972?

(2) If not to what relief is the workman entitled and from what date?"

2. In this reference the written statements were filed by both sides and the case proceeded along its course. On two successive dates when the reference was fixed for steps neither the workman nor anybody on his behalf was present nor any step was taken by them. No sufficient cause was shown to the Court from the side of the workman as to their failure to be present or to take necessary steps. The learned Advocate representing the employers submits that they are not interested to proceed with the case any more. It is an old case of 1974. In the absence of the workmen and on account of their default to take any steps in the matter I am inclined to think that the workmen are no more interested to prosecute their case presumably because of the non-existence of the industrial dispute any more. So, I am left with no other alternative but to pass a 'no dispute' award.

3. The industrial dispute involved in this reference is therefore disposed on a 'no dispute award'.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

[No. L-2012/49/74-LRII]

G. C. SAXENA, Under Secy.

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4538.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1974 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management Messrs. Ballarpur Colliery of Coal Mines Authority Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd September, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY.

Reference No. CGIT-16 of 1975

Employers in relation to the management of M/s Ballarpur Colliery of Coal Mines Authority Ltd.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri J. D. Sirmukaddam, Law Officer, Coal Mines Authority Ltd., Western Div., Nagpur.

Shri S. N. Katiyar, Assistant Chief Personnel Officer, Coal Mines Authority Ltd., Wardha.

For the Workmen.—Shri S. Mazhar, President, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Chandrapur.

Industry.—Coal Mines.

State—Maharashtra.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, have by their Order No. L-22012/13/74-LRII/DIII A., dated the 10th March, 1975, made in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Ballarpur Colliery of M/s Coal Mines Authority Ltd., Post Office Ballarpur, District Chanda (Maharashtra), and their workman, in respect of the matters specified in the following schedule :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Ballarpur Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Ballarpur, District Chanda (Maharashtra) in terminating the services of Shri Krishna, son of Andhoo, Drill Machine Driver, is justified ? If not to what relief is the workman entitled".

2. After the receipt of the reference, notices were issued to the parties for filing their respective written statements While the Union filed its written statement of claim, the management wanted time to file its written statement and prayed this Tribunal to direct the workman to furnish particulars and documents in support of his contentions made in the statement of claim.

3. The matter was fixed for hearing on two or three occasions. However, at the hearing fixed on 27th August, 1975, at Nagpur, the parties have filed settlement dated 22-8-1975 arrived at by them, and pray that an Award be made in terms of the settlement reached by them.

4. I have gone through the terms of the settlement and I feel that the settlement is fair and just and puts at rest the dispute between the parties. The Award is therefore passed in terms of settlement. A copy of the settlement is Annexure-I to this award and forms a part of the Award.

The reference is disposed of in terms of the settlement. No order as to costs.

30th August, 1975

B. RAMLAL KISHEN, Presiding Officer.

ANNEXURE I

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Representing Employer.—Shri S. B. Katiyar, Asstt. Chief Personnel Officer, Coal Mines Authority Ltd., Wardha Valley, Chandrapur.

Representing Workmen—Shri S. Mazhar, President, Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Wardha Valley Area, Chandrapur.

SHORT RECITAL

Shri Krishna Andhoo who was working as a Drill Machine Khalasi was dismissed after due enquiry with effect from 18-1-74 by the Management of Ballarpur Colliery for refusing to give normal workload. After failure of Conciliation report regarding his dismissal the dispute relating thereto has been referred to CGIT, Bombay, for adjudication. The Union representing the workman approached the Management for settling the dispute bilaterally. Consequently the discussions between the Management and the Union were held, as a result of which it has been agreed to settle the dispute on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

1. The Union and Shri Krishna Andhoo regretted for the misconduct committed by the latter and assured to give normal workload of a Drill Khalasi

2. The Management agrees to appoint Shri Krishna Andhoo a fresh as Drill Khalasi in any of the collieries of Wardha Valley Area within 7 days of the receipt of the Consent Award.

3. The Union agrees that this is the full and final settlement and they do not have any claim whatsoever, for the period of unemployment of Shri Krishna Andhoo.

4. The Management and the Union agree to file before the Hon. Industrial Tribunal this Settlement with the prayer to give Consent Award in terms of the above agreement, in the case No. 16 of 1975.

S. MAZHAR, President

Samyukta Khadan Mazdoor Sangh, Chandrapur.

S. B. Katiyar, ACPO.

Coal Mines Authority Ltd., Wardha Valley Chandrapur.

Witnesses :

1. K. Parvez, Stenographer.

2. A. M. Bogawar, Clerk.

Dated : 22nd August, 1975.

[No. L 22012/13/74-LRII]

S.O. 4539.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Western Kajora Colliery of Coal Mines Authority and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th September, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT :

Shri E. K. Moidu Presiding Officer

REFERENCE NO. 50 OF 1975

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Kajora Colliery of Coal Mines Authority Limited.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of the employers.—Sri N. Das, Advocate, with Shri B. N. Lala, Asstt. Chief Personnel Officer & Shri A. N. Chatterjee, Industrial Relations Officer.
On behalf of Workmen.—

ABSENT

State : West Bengal Industry : Coal Mines

ORDER

The following Reference was made to this Tribunal for adjudication by the Government of India, vide the Order of Ministry of Labour in its communication No. L-19012/6/6/75/D. IIIB dated 22nd July, 1975 :

"Whether the action of the management of Western Kajora Colliery of Coal Mines Authority Limited, Post Office Raniganj, District Burdwan, in stopping Shrimati Lallta Devi, Loading Kamin, from work, with effect from 22nd November, 1973 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. Summons was issued to the Joint-Secretary, Colliery Mazdoor Congress, Bittan House, Tarun Palli Road, Ushagram, P.O. Asansol, District Burdwan, as well as the Coal Mines Authority Limited, in pursuance to the Reference.

3. On receipt of the summons, the Joint Secretary, referred to above filed a verified petition dated 1-9-1975 stating that Smt. Lalita Devi had already been reinstated to the service and therefore the Union do not propose to proceed with the case against the Coal Mines Authority Limited. The Coal Mines Authority Limited did not file any written statement in this proceeding.

4. In the result, the reference is rejected without any adjudication of the dispute.

Accordingly no award is made.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

Calcutta.

Dated : The 19th September, 1975.

[No. L19012/6/75/DIII/B]
S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.).

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 18 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4540.—दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 11 के अन्तर्गत सूचना जिसे दिल्ली डेवलपमेंट (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना) नियम 1959 के नियम 5 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि :—

(ए) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली डवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जोन ए-26 (लाल किला) तथा ए-27 (राजघाट) के क्षेत्रीय विकास योजना चित्र को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(बी) स्वीकृत योजना चित्र की प्रति कार्यालय दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन डी ब्लाक, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्यशील दिनों में प्रातः 11-00 बजे से अपराह्न 3-00 बजे तक निरीक्षण हेतु प्राप्य है।

[सं० एफ 16 (117) /75-एम०पी०]
हृदय नाथ फोतेदार, सचिव.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi the 18th October, 1975

S.O. 4540.—Notice under Section 11 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959. Notice is hereby given that :—

(a) The Central Government have under Sub-section (2) of Section 9 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), approved the Zonal Development Plan for Zones A-26 (Red Fort) and A-27 (Raj Ghat).

(b) A copy of the plan as approved may be inspected at the office of the Delhi Development Authority, Vikas Bhawan, 'D' Block, Indraprastha Estate, New Delhi-1, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days.

[No. F. 16(117)/75-MP.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI.
AND PUBLIHSED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1975.